



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2018/अग्रहायण 9, 1940

No. 458]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2018/AGRAHAYANA 9, 1940

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 30 नवम्बर, 2018

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018

सं.सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2018/48.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15अ, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अ और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19अक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निपटारे की शर्तों आदि तथा निपटारे की प्रक्रिया और उनसे जुड़े या उनसे आनुषंगिक विषयों के संबंध में प्रावधान करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

### अध्याय-I

#### प्रारंभिक

#### संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
- (2) वे 1 जनवरी, 2019 को प्रवृत्त (लागू) होंगे।

## परिभाषाएँ

2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए नियत हैं, और उनके सजातीय पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,—

- (क) “अधिनियम” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;
- (ख) “कथित चूक” से प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के किसी प्रावधान का कथित या संभावित उल्लंघन अभिप्रेत है;
- (ग) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) “पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल” से ऐसा पैनल अभिप्रेत है, जिसमें बोर्ड के दो या दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य हों;
- (ङ) “प्रतिभूति विधियों” से अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), किसी अन्य विधि के संबंधित प्रावधान (जहाँ तक वे बोर्ड के दायरे में आते हों) और उनके तहत बनाए गए संबंधित नियम तथा विनियम अभिप्रेत हैं;
- (च) “निर्धारित कार्यवाहियों” से ऐसी कार्यवाहियाँ अभिप्रेत हैं, जो, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 11, धारा 11ख, धारा 11घ, धारा 12 की उप-धारा (3) या धारा 15अ अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क या धारा 23अ अथवा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 या धारा 19ज के तहत, प्रतिभूति विधियों के उल्लंघन के लिए, बोर्ड द्वारा शुरू की जा सकती हों अथवा शुरू की गई हों और जो बोर्ड या किसी अन्य फोरम के समक्ष लंबित हों;
- (छ) “न्यायाधिकरण” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ट के तहत स्थापित प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित, किंतु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, कंपनी अधिनियम, 2013 या उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानूनी संशोधन या पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए नियत हों।

## अध्याय-II

### निपटारे के लिए आवेदन

#### आवेदन

**3.** (1) जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई निर्धारित कार्यवाहियाँ शुरू की गई हों और लंबित हों या शुरू की जा सकती हों, वह व्यक्ति बोर्ड के पास अनुसूची-I के भाग-क में निर्धारित किए गए फॉर्म में आवेदन कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत किए गए आवेदन के साथ अनुसूची-I के भाग-ख में यथा निर्धारित अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) आवेदन फीस लगाई जाएगी और अनुसूची-I के भाग-ग में यथा निर्धारित वचन तथा अधित्यजन (वेवर) प्रस्तुत किए जाएंगे:

परंतु यह कि आवेदन को नामंजूर किए जाने या वापस लिए जाने से प्रस्तुत किए वचनों तथा अधित्यजनों [जो किसी कानूनी कार्यवाही को शुरू करने या जारी रखने या दोबारा शुरू करने के संबंध में सीमा (लिमिटेशन) या अतिविलंब (लैचिज़) की बाबत प्रस्तुत किए गए हों] की सतत वैधता पर और अनुसूची-I के भाग-ग में प्रस्तुत किए गए वचनों तथा अधित्यजनों (वेवर) के पैरा 12 के उप-पैरा (घ), (ङ), (च) एवं (छ) के तहत प्रस्तुत किए गए अधित्यजनों (वेवर) की सतत वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे वचनों तथा अधित्यजनों (वेवर) के अध्यक्षीन, बोर्ड या आवेदक, ऐसी कार्यवाहियाँ शुरू करने या जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा जो विधि के अनुसार उपयुक्त हों।

(3) आवेदक कथित चूक (चूकों) के संबंध में आवेदन में पूरा-पूरा और सही-सही प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करेगा:

परंतु यह कि, किन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत, उसी वाद हेतुक के संबंध में भारत में या भारत के बाहर चल रही या पूरी हो चुकी किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आवेदक के खिलाफ सिद्ध हो चुके या उसके द्वारा स्वीकार किए जा चुके तथ्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे निपटारा किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के संबंध में आवेदक द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

(4) आवेदक उन सभी कार्यवाहियों के निपटारे के लिए एक आवेदन करेगा जो उसी वाद हेतुक के संबंध में शुरू की गई हों या शुरू की जा सकती हों।

(5) जो आवेदन पूरी तरह न भरा गया हो या जिसके साथ अपेक्षित दस्तावेज न लगाए गए हों या जो इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो, वह आवेदन आवेदक को लौटा दिया जाएगा।

(6) जिस आवेदक का आवेदन उप-विनियम (5) के तहत लौटा दिया गया हो, वह आवेदक बोर्ड से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, अपेक्षित दस्तावेजों सहित पूरी तरह भरा गया और संशोधित आवेदन प्रस्तुत करेगा जो इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो:

परंतु यह कि आवेदक को कार्यवाहियों के एक ही चरण [जैसा अनुसूची-II की सारणी-I में दर्शाया गया है] के दौरान कथित चूक के संबंध में आवेदन करने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(7) जहाँ आवेदक संघ (असोसिएशन) या फर्म या निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) या सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) हो, वहाँ ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन और वचन तथा अधित्यजन प्रस्तुत किए जाएंगे, जो ऐसी फर्म या संघ या निगमित निकाय के कारबार का प्रभारी हो तथा जिस पर उसे चलाने की जिम्मेदारी हो, और जिसका पालन करने के लिए फर्म या संघ, निगमित निकाय तथा कोई चूककर्ता अधिकारी भी बाध्य होगा।

**स्पष्टीकरण.** - इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, पद “चूककर्ता अधिकारी” (अधिकारी जो व्यतिक्रमी है) का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (60) में दिया हुआ है।

(8) प्रकटीकरणों से संबंधित चूकों के निपटारे के लिए आवेदन, जहाँ तक संभव हो, अपेक्षित प्रकटीकरण करने के बाद ही किया जाएगा।

### **परिसीमा (लिमिटेशन)**

4. (1) बोर्ड के समक्ष लंबित किसी निर्धारित कार्यवाही के संबंध में किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि आवेदन कारण बताओ सूचना की तामील किए जाने की तारीख या कारण बताओ सूचना के संबंध में बाद में भेजी जाने वाली सूचना (सूचनाओं) की तामील किए जाने की तारीख (जो भी बाद में हो) से साठ दिनों के बाद किया जाता है।

(2) उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड आवेदन पर विचार कर सकेगा, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन दाखिल न किए जाने का पर्याप्त कारण था और उसके साथ अनुसूची-I के भाग-ख में यथा निर्धारित अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस लगाई जाए:

परंतु यह कि, जहाँ आवेदन उप-विनियम (1) में निर्धारित अवधि के समाप्त होने से साठ कलेंडर दिनों के बाद किया जाए, वहाँ इन विनियमों की अनुसूची-II के अनुसार तय की जाने वाली निपटारे की रकम में पच्चीस प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी:

परंतु यह और कि, देरी से प्रस्तुत किए गए किसी भी ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, जो उप-विनियम (1) में निर्धारित अवधि के समाप्त होने से एक सौ बीस कलेंडर दिनों के बाद या पहली सुनवाई के बाद, जो भी पहले हो, दाखिल किया जाए।

(3) इस विनियम के प्रावधान न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के मामले में लागू नहीं होंगे।

## **अध्याय-III**

### **निपटारे का दायरा**

#### **निपटारे की कार्यवाहियों का दायरा**

5. (1) किन्हीं निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे के लिए किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि:

- (क) उसी कथित चूक के संबंध में पहले किया गया आवेदन नामंजूर किया जा चुका हो;
- (ख) किसी वाद हेतुक के संबंध में कोई लेखापरीक्षा (ऑडिट) या अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) या निरीक्षण या जाँच, यदि कोई हो, पूरी न हुई हो (ऐसे आवेदनों को छोड़कर जिनमें गोपनीयता की मांग की गई हो); या
- (ग) प्रतिभूति विधियों के तहत जारी किए गए आदेश के तहत देय धनराशियों की वसूली प्रतिभूति विधियों के तहत की जानी हो।

(2) बोर्ड किसी निर्धारित कार्यवाही का निपटारा नहीं कर सकेगा, यदि उसकी यह राय हो कि कथित चूक,-

- i. का प्रभाव पूरे बाजार पर पड़ा हो,
- ii. से बड़ी संख्या में निवेशकों को नुकसान हुआ हो, या
- iii. से बाजार की सत्यनिष्ठा प्रभावित हुई हो।

(3) उपरोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी निर्धारित कार्यवाही का निपटारा करने के लिए बोर्ड, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकेगा,-

- (क) क्या आवेदक ने देय रकम लौटा दी है या प्रत्यर्पित (डिस्मॉर्ज) कर दी है, और जिससे बोर्ड संतुष्ट है;
- (ख) क्या आवेदक ने प्रतिभूति विधियों का पालन करते हुए निवेशकों को बाहर निकलने या खरीदने का विकल्प दिया है, और जिससे बोर्ड संतुष्ट है;
- (ग) क्या आवेदक प्रतिभूति विधियों का अथवा प्रतिभूति विधियों के तहत पारित किए गए किसी आदेश या निदेश का पालन कर रहा है, और जिससे बोर्ड संतुष्ट है;
- (घ) कोई अन्य कारक जो बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझा जाए।

(4) उप-विनियम (1) तथा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड ऐसे मामलों में निर्धारित कार्यवाहियों का निपटारा नहीं कर सकेगा, जहाँ आवेदक इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) हो, भगोड़ा आर्थिक अपरोधी हो अथवा उसने प्रतिभूति विधियों के तहत देय कोई फीस या उस पर लगाई गई कोई शास्ति (पेनल्टी) अदा करने में चूक की हो।

(5) इन विनियमों में दी हुई किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि उससे पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के उस अधिकार को सीमित किया गया है, जिसके तहत वह आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा जाँच किए जाने के बिना ही किसी निर्धारित कार्यवाही के संबंध में किसी आवेदन पर विचार कर सकता है या उसे नामंजूर कर सकता है।

### **आवेदन नामंजूर किया जाना**

**6. (1)** किसी आवेदन को निम्नलिखित आधारों पर किसी भी समय नामंजूर किया जा सकेगा:

- (क) जहाँ आवेदक बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचनाएँ आदि प्राप्त करने या उनके संबंध में उत्तर देने से इनकार कर दे;
- (ख) जहाँ आवेदक बोर्ड द्वारा मांगी गई जानकारी, दस्तावेज, आदि प्रस्तुत न करे या प्रस्तुत करने में देरी करे;
- (ग) जहाँ आवेदक (जिससे हाजिर होने की अपेक्षा की गई हो), एक से अधिक बार आंतरिक समिति के समक्ष हाजिर न हो;
- (घ) जहाँ आवेदक अनुसूची-1 के भाग-ग में उल्लिखित वचनों और छूटों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करे;
- (ङ) जहाँ आवेदक विनियम 15 के उप-विनियम (2) के खंड (क) में निर्धारित अवधि के भीतर निपटारे की रकम प्रेषित न करे और/या वचन तथा छूटों का पालन न करे।

(2) उप-विनियम (1) के तहत की जाने वाली नामंजूरी की सूचना आवेदक को दी जाएगी:

परंतु यह कि आवेदक उन अधित्यजनों (वेवर) का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा, जो किसी कानूनी कार्यवाही को शुरू करने या जारी रखने या दोबारा शुरू करने के संबंध में परिसीमा (लिमिटेशन) या अतिविलंब (लैचिज़) की बाबत प्रस्तुत किए गए हों और जो अनुसूची-1 के भाग-ग में प्रस्तुत किए गए वचनों तथा अधित्यजनों (वेवर) के पैरा 12 के उप-पैरा (घ), (ङ), (च) एवं (छ) के तहत प्रस्तुत किए गए हों।

### **आवेदन वापस लिया जाना**

7. (1) विनियम 15 के तहत पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के निर्णय की सूचना दिए जाने से पहले किसी भी समय आवेदन वापस लिया जा सकेगा।

(2) जो आवेदक उप-विनियम (1) के तहत आवेदन वापस ले लेता हो, उसे उसी चूक के संबंध में दूसरा आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह कि, जैसी सिफारिश उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा की जाए, ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकेगा, बशर्ते कि इन विनियमों की अनुसूची-11 के अनुसार तय की गई निपटारे की रकम कम से कम पचास प्रतिशत बढ़ा दी जाए।

### **निर्धारित कार्यवाहियों के संबंध में लंबित आवेदन का प्रभाव**

8. (1) किन्हीं निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे के लिए आवेदन दाखिल करने से कार्यवाहियों के जारी रहने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन के संबंध में निपटारा नहीं कर दिया जाता।

(2) जहाँ आवेदन ऐसी कार्यवाहियों के मामले में दाखिल किया जाता हो जो आवेदक के खिलाफ शुरू की जा सकती हों, वहाँ ऐसी कार्यवाहियाँ तब तक शुरू नहीं की जाएंगी जब तक आवेदन नामंजूर न कर दिया जाए या वापस न ले लिया जाए:

परंतु यह कि, आवेदन दाखिल किए जाने से किन्हीं कार्यवाहियों को शुरू किए जाने पर रोक नहीं लगेगी, जहाँ तक वे निवेशकों के हितों के संरक्षण हेतु और प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) की सत्यनिष्ठा को कायम रखने हेतु अंतरिम सिविल तथा प्रशासनिक निदेशों को जारी करने के प्रयोजनार्थ जरूरी समझी जाएं।

**स्पष्टीकरण.-** जहाँ कोई कार्यवाही कई व्यक्तियों के खिलाफ लंबित हो या शुरू की जानी हो किंतु निपटारे का आवेदन सभी द्वारा दाखिल न किया गया हो बल्कि केवल एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा ही दाखिल किया हो, वहाँ ऐसे आवेदन को दाखिल किए जाने से उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाहियों को शुरू किए जाने, जारी रखने तथा उनका निपटारा किए जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसने निपटारे के लिए आवेदन दाखिल न किया हो और ऐसी कार्यवाहियों में उस आवेदक के खिलाफ की गई किन्हीं प्रतिकूल टिप्पणियों का उस आवेदक पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, यह ऐसे आवेदक द्वारा दाखिल किए गए निपटारे के आवेदन के परिणाम पर निर्भर करेगा।

## **अध्याय-IV**

### **निपटारे की शर्तें आदि**

#### **निपटारे की शर्तें आदि**

9. (1) निपटारे की शर्तों आदि के अंतर्गत अनुसूची-11 में निर्धारित दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) के अनुसार निपटारे की रकम और/या गैर-आर्थिक शर्तें शामिल हो सकेंगी।

(2) गैर-आर्थिक शर्तों में निम्नलिखित शर्तें शामिल हो सकेंगी:

- (क) एक निर्धारित अवधि के लिए कारबार संबंधी क्रियाकलापों को निलंबित करना या उन्हें बंद करना;
- (ख) प्रबंध-मंडल से बाहर निकलना;
- (ग) आवेदक के कुछ करने या कुछ न करने के कारण प्रत्यर्पण (डिस्मॉर्जमेंट);
- (घ) निर्धारित अवधियों के लिए, किसी मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के भागीदार या अधिकारी या निदेशक के रूप में अथवा किसी ऐसी कंपनी के अधिकारी या निदेशक के रूप में कार्य करने से रोकना, जिसकी किसी वर्ग की प्रतिभूतियों का विनियमन बोर्ड द्वारा किया जाता हो;
- (ङ) जहाँ प्रतिभूतियाँ कपटपूर्ण ढंग से निर्गमित (इश्यू) की गई हों, वहाँ प्रतिभूतियों को रद्द करना और धारिताओं (होलिडिंग्स) को कम करना [जिसमें शामिल है ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत मिले बोनस शेयरों (यदि कोई हों) को भी रद्द करना और यदि कोई लांभांश (डिविडेंड) मिला हो, तो उसे भी वापस करना];
- (च) प्रतिभूतियों की अवरुद्धता (लॉक-इन);
- (छ) भविष्य में प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के उल्लंघनों को रोकने के लिए बेहतर नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ लागू करना और आंतरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं आदि की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र परामर्शदाता को नियुक्त आदि करने के लिए सहमति देना;
- (ज) मध्यवर्तियों और प्रतिभूति बाजार की बुनियादी संस्थाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशन्स) के कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं शिक्षण प्रदान करना;
- (झ) आंतरिक लेखापरीक्षा (ऑडिट) और रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षाओं का पालन करने के लिए सहमत होना ।
- (3) निपटारे की रकम [कानूनी खर्चों और प्रत्यर्पित (डिस्मॉर्ज) रकम को छोड़कर] भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी
- (4) विनियम 3 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित आवेदन फीस और कानूनी खर्च, यदि कोई हों, जो निपटारे की रकम का हिस्सा हों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की साधारण निधि (जनरल फंड) में जमा किए जाएंगे ।

**स्पष्टीकरण.-** कानूनी खर्चों में ऐसे अनुमानित खर्च (जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए) शामिल हैं, जो विनियम 24 के उप-विनियम (2) के तहत न्यायाधिकरण या न्यायालय से समुचित आदेश प्राप्त करने के लिए किए जाएँ ।

- (5) आवेदक द्वारा कमाए गए मुनाफे या टाले गए नुकसान की रकम (जो निपटारे की शर्तों आदि के तौर पर प्रत्यर्पित की जा सकेगी) निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में जमा की जाएगी ।

#### **निपटारे की शर्तें आदि तय करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारक**

**10.** (1) निपटारे की शर्तें आदि तय करते समय, अनुसूची-II में उल्लिखित कारकों पर विचार किया जा सकेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं किंतु जो इन तक ही सीमित नहीं हैं:

- (क) निर्धारित कार्यवाही, अन्वेषण, निरीक्षण या लेखापरीक्षा (ऑडिट) के दौरान आवेदक का आचरण;
- (ख) उस मामले में आवेदक की भूमिका, जहाँ कथित चूक व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई हो;
- (ग) कथित चूकों का स्वरूप, उनकी गंभीरता और उनका प्रभाव;
- (घ) क्या प्रतिभूति विधियों का पालन न किए जाने के लिए आवेदक के खिलाफ कोई अन्य कार्यवाही लंबित है या पूरी हो गई है;
- (ङ) आवेदक द्वारा निवेशकों को कितना नुकसान आदि पहुंचाया गया और/या उसने कितना मुनाफा कमाया;

- (च) कथित चूक होने के बाद से, भविष्य में चूकों या गलतियों को कम करने के लिए, क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं;
- (छ) आवेदक द्वारा पालन के संबंध में प्रस्तावित समय-सारणी;
- (ज) पालन न किए जाने या पालन देरी से किए जाने के कारण किसी व्यक्ति को होने वाले आर्थिक लाभ;
- (झ) ऐसी शर्तें जो उसी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को भविष्य में पालन न करने से रोकने के लिए जरूरी हों;
- (ञ) निवेशकों के उस दावे को पूरा करना, जो उन्हें देय धनराशि के भुगतान या उन्हें प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी (डिलीवरी) किए जाने के संबंध में हो;
- (ट) कोई अन्य प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई जो उसी उल्लंघन के लिए आवेदक के खिलाफ की गई हो;
- (ठ) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनज़र कोई अन्य जरूरी कारक।

### अध्याय-V

#### समितियाँ

##### उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति

11. (1) बोर्ड निपटारे की शर्तों आदि के संबंध में विचार करने के लिए और सिफारिश देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन करेगा।

(2) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति में एक ऐसा न्यायिक सदस्य होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो और ऐसे तीन बाहरी विशेषज्ञ होंगे जो प्रतिभूति बाजार अथवा उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक विषयों में विशेषज्ञता रखते हों।

(3) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, जो दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(4) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की बैठक के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा।

स्पष्टीकरण. - बैठक में वह बैठक भी शामिल है जो ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से की जाती है।

(5) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति अपनी बैठकें उसी प्रकार आयोजित करेगी, जैसा बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जाए:

परंतु यह कि:

- (i) जहाँ उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का कोई सदस्य बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर देता हो, वहाँ शेष दो या दो से अधिक सदस्य निपटारे की शर्तों आदि के संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकेंगे;
- (ii) जहाँ कोई सर्वसम्मति या बहुमत न बन पाए, वहाँ न्यायिक सदस्य द्वारा की गई सिफारिश को उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिश समझा जाएगा और न्यायिक सदस्य के बैठक में हिस्सा लेने से इनकार किए जाने पर, शेष दो या दो से अधिक सदस्यों की सिफारिशों को पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा; और



- (iii) जहाँ उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के सभी सदस्य या एक सदस्य को छोड़कर बाकी सभी सदस्य किसी आवेदन के संबंध में बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर देते हों, वहाँ बोर्ड दूसरी उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा।

### आंतरिक समिति (समितियाँ)

12. (1) आंतरिक समिति (समितियों) का गठन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।  
 (2) आंतरिक समिति (समितियों) में बोर्ड का ऐसा अधिकारी होगा, जो मुख्य महाप्रबंधक के स्तर से नीचे के स्तर का न हो और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।

## अध्याय-VI

### निपटारे की प्रक्रिया

#### आंतरिक समिति के समक्ष कार्यवाहियाँ

13. (1) इन विनियमों में अन्यथा जो प्रावधान किए गए हैं, उनके सिवाय, आवेदन आंतरिक समिति के पास यह जांचने के लिए कि क्या कार्यवाहियों का निपटारा किया जा सकता है और यदि किया जा सकता है तो इन विनियमों के अनुसार निपटारे की शर्तें आदि तय करने के लिए भेजा जाएगा।

#### (2) आंतरिक समिति:

- (क) कथित चूक (चूकों) के संबंध में ऐसी संबंधित जानकारी, दस्तावेज, आदि मंगा सकेगी जो आवेदक के पास हों या जो आवेदक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हों;

**स्पष्टीकरण.-** इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात आवेदक को ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करेगी जिसके तहत वह निपटारे की कार्यवाहियों में आधार बनाने के लिए बोर्ड से जानकारी मांग सके या बोर्ड से किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मंगाने की अपेक्षा कर सके या बोर्ड से यह निवेदन कर सके कि उसे वह जानकारी भी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए जो आवेदन में पहले प्रकट न की गई हो, और जो आवेदन करते समय आवेदक को पता हो या जो अच्छी तरह जाँच किए जाने पर आवेदक को पता चल सकती हो।

- (ख) आवेदक को अपने समक्ष स्वयं हाजिर होने के लिए कह सकेगी:

परंतु यह कि आवेदक का विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि आवेदक की ओर से प्रतिनिधित्व कर सकेगा;

**स्पष्टीकरण.-** इस खंड के तहत स्वयं हाजिर होने में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से हाजिर होना शामिल है, जैसी मंजूरी आंतरिक समिति द्वारा दी जाए।

- (ग) आवेदक को निपटारे की संशोधित शर्तें आदि, आंतरिक समिति की बैठक की तारीख से दस कार्य-दिवसों के भीतर, प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी :

परंतु यह कि दस कार्य-दिवसों के बाद किंतु बीस कार्य-दिवसों के भीतर प्राप्त हुई निपटारे की संशोधित शर्तें आदि पर विचार किया जा सकेगा, बशर्ते कि निपटारे की रकम (जिसकी सिफारिश की गई हो) में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए।

- (3) निपटारे की प्रस्तावित शर्तें आदि, यदि कोई हों, उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के समक्ष रखी जाएंगी।

### उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के समक्ष कार्यवाहियाँ

14. (1) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति इसके समक्ष रखी गई निपटारे की प्रस्तावित शर्तों आदि के साथ-साथ:

- (क) आवेदक के आवेदन, वचन और अधित्यजनों (वेवर);
- (ख) विनियम 10 में निर्धारित कारकों;
- (ग) आवेदक द्वारा प्रस्तावित निपटारे की शर्तों आदि या निपटारे की संशोधित शर्तों आदि;
- (घ) रिकॉर्ड में उपलब्ध किसी अन्य संबंधित सामग्री;

पर विचार करेगी।

(2) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति निपटारे की शर्तों आदि को संशोधित करने की मांग कर सकेगी और आवेदन वापस आंतरिक समिति को भिजवा सकेगी।

(3) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिशें पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के समक्ष रखी जाएंगी।

### उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिश पर कार्रवाई

15. (1) पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और उन्हें स्वीकार या नामंजूर कर सकेगा:

परंतु यह कि जहाँ उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की निर्धारित कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने संबंधी सिफारिशों को नामंजूर किया जाता हो, वहाँ पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल उन सिफारिशों को नामंजूर किए जाने के कारणों को दर्ज करेगा:

परंतु यह और कि जहाँ उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की निर्धारित कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने संबंधी सिफारिश को नामंजूर किया जाता हो, वहाँ पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के ऐसे निर्णय के बारे में आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(2) जहाँ पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की निर्धारित कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने संबंधी सिफारिश को स्वीकार कर लेता हो, वहाँ आवेदक को पैनल के निर्णय के सात कार्य-दिवसों के भीतर मांग की सूचना (नोटिस ऑफ डिमांड) जारी की जाएगी और आवेदक,-

(क) मांग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह कलेंडर दिनों के भीतर, निपटारे की रकम [जो निपटारे की शर्तों आदि का हिस्सा हो] प्रेषित करेगा, और यह अवधि पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा, ऐसे कारणों से जिन्हें दर्ज किया जाए, पंद्रह कलेंडर दिनों तक बढ़ाई जा सकेगी

**स्पष्टीकरण.**- निपटारे की रकम 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड' के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के जरिए या एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए निर्धारित बैंक खाते में सीधे जमा करके या फिर भुगतान के किसी अन्य प्राधिकृत माध्यम से प्रेषित की जाएगी:

परंतु यह कि, जहाँ निपटारे की रकम मांग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस कलेंडर दिनों के पश्चात् और ऐसी प्राप्ति से नब्बेवें दिन तक प्रेषित की जाती है, वहाँ आवेदक द्वारा अदा की जाने वाली

निपटारे की रकम में, मांग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से निपटारे की रकम अदा किए जाने की तारीख तक, प्रतिवर्ष छह प्रतिशत की दर से साधारण व्याज लगाकर बढ़ोतरी कर दी जाएगी:

परंतु यह और कि, किसी भी दशा में इस प्रकार प्रेषित की जाने वाली निपटारे की रकम मांग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से नब्बेवें कलेंडर दिन के पश्चात् स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) उसे दिए गए समय के भीतर, निपटारे की अन्य शर्तों आदि, यदि कोई हों, को पूरा करेगा / का पालन करने का वचन लिखित रूप में देगा।

(3) जहाँ पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश की गई निपटारे की शर्तों आदि पर निर्धारित कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने संबंधी उसकी सिफारिश को स्वीकार न करता हो, वहाँ पैनल निपटारे की शर्तों आदि की दोबारा जाँच करने के लिए आवेदन को लौटा सकेगा और तत्पश्चात् आंतरिक समिति और उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो मूल आवेदन के मामले में लागू है।

## अध्याय-VII

### संक्षिप्त निपटारे की प्रक्रिया

#### संक्षिप्त निपटारे की प्रक्रिया

**16.** (1) अध्याय-VI में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारित कार्यवाही शुरू करने से पहले, बोर्ड निम्नलिखित चूकों (डिफॉल्ट) के संबंध में, अनुसूची-III के भाग-क में यथा निर्धारित फॉर्मेट में संक्षिप्त निपटारे की सूचना (नोटिस) जारी कर सकेगा, जिसमें नोटिसी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अध्याय-II के तहत निपटारे का आवेदन दाखिल करे तथा निपटारे की रकम जमा कराए और/या उन अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि के संबंध में वचन प्रस्तुत करे या उन अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि का पालन करे, जिसका (जिनका) उल्लेख निर्धारित कार्यवाही (कार्यवाहियों) की बाबत संक्षिप्त निपटारे की सूचना (नोटिस) में किया जाए,-

- i. देरी से प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करना, जिसमें विवरणियाँ, रिपोर्ट, दस्तावेज, आदि को देरी से दाखिल करना शामिल है;
- ii. जिन प्रादेशिक (रीज़नल) स्टॉक एक्सचेंजों का निकास (एग्जिट) हो चुका है, केवल उन प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) न करना;
- iii. निर्धारित फॉर्मेटों में प्रकटीकरण न करना;
- iv. कानूनी प्रावधानों की किन्हीं अपेक्षाओं का या बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करने में देरी करना;
- v. ऐसी अन्य चूकें (डिफॉल्ट), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ:

परंतु यह कि, निर्धारित कार्यवाही (कार्यवाहियों) का निपटारा इस अध्याय के तहत नहीं किया जाएगा, यदि बोर्ड की राय में, आवेदक तथ्यों का पूरा-पूरा और सही-सही प्रकटीकरण करने में असफल रहा हो या उस प्रकार सहयोग प्रदान करने में असफल रहा हो, जैसी अपेक्षा की गई हो।

(2) निपटारे की सूचना (नोटिस) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पास नोटिसी के खिलाफ की जाने वाली प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई में परिवर्तन करने की शक्ति होगी और निपटारे की सूचना (नोटिस) नोटिसी को निपटारे की मांग करने का या किसी प्रवर्तन कार्रवाई से बचने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) नोटिसी निपटारे की सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से तीस कलेंडर दिनों के भीतर,—

(क) अनुसूची-1 के भाग-क में निर्धारित फॉर्म में निपटारे का आवेदन दाखिल कर सकेगा, जिसके साथ अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) आवेदन फीस (जैसी के भाग-ख में निर्धारित की गई है) लगाई जाएगी तथा वचन और अधित्यजन (वेवर) [जैसा अनुसूची-1 के भाग-ग में निर्धारित किया गया है] भी लगाए जाएंगे;

(ख) निपटारे की रकम [जिसका उल्लेख निपटारे की सूचना (नोटिस) में किया गया हो] प्रेषित कर सकेगा;

(ग) अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि [जिनका उल्लेख निपटारे की सूचना (नोटिस) में किया गया हो] का, यथास्थिति, पालन कर सकेगा या पालन करने का वचन दे सकेगा; और

(घ) निपटारे का आवेदन दाखिल करते समय, निपटारे की रकम [जैसा निपटारे की सूचना (नोटिस) में सूचित की गई हो] की गणना में सुधार की मांग कर सकेगा और ऐसे सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा तथा रकम बोर्ड का निर्णय प्राप्त होने की तारीख से तीस कलेंडर दिनों के भीतर प्रेषित की जाएगी:

परंतु यह कि, बोर्ड ऐसे कारणों से जो दर्ज किए जाएं, निपटारे का आवेदन दाखिल करने के संबंध में, उस निपटारे की रकम को प्रेषित करने के संबंध में और/या उन गैर-आर्थिक शर्तों आदि में से किसी शर्त आदि की बाबत वचन प्रस्तुत करने के संबंध में या उन गैर-आर्थिक शर्तों आदि में से किसी शर्त आदि का पालन करने के संबंध में अधिक से अधिक पंद्रह कलेंडर दिनों का और समय प्रदान कर सकेगा, जिसका (जिनका) उल्लेख निपटारे की सूचना (नोटिस) में किया गया हो।

(4) निपटारे की सूचना (नोटिस) में यथा उल्लिखित निपटारे की रकम के प्रेषण से और गैर-आर्थिक शर्तों आदि, यदि कोई हों, की बाबत प्रस्तुत किए गए वचन से या गैर-आर्थिक शर्तों आदि के पालन से संतुष्ट हो जाने पर, बोर्ड विनियम 23 के तहत निपटारे का आदेश पारित करेगा।

**17.** इन विनियमों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ नोटिसी बोर्ड का निर्णय सूचित किए जाने से पहले किसी भी समय, इस अध्याय के तहत निपटारे का आवेदन दाखिल नहीं करता या निपटारे की रकम प्रेषित नहीं करता और/या बोर्ड के अनुसार संतोषजनक रूप से अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि का पालन नहीं करता या निपटारे का आवेदन वापस ले लेता हो, वहाँ निर्धारित कार्यवाहियाँ शुरू की जा सकेंगी, और ऐसे नोटिसी को केवल उन्हीं कार्यवाहियों की बाबत निपटारे का आवेदन दाखिल करने की अनुमति होगी, जो, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी (अडजूडिकेटिंग ऑफिसर) या बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियाँ पूरी हो जाने के पश्चात् न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) के समक्ष लंबित हों।

## अध्याय-VIII

### निपटारे की सूचना (नोटिस)

#### निपटारे की सूचना (नोटिस)

**18.** (1) कारण बताओ सूचना (नोटिस टू शो काँज़) जारी करने से पहले, अनुसूची-III के भाग-ख में निर्धारित फॉर्मेट में निपटारे की सूचना (नोटिस), जिसके अंतर्गत संभावित आरोपों के सार और प्रवर्तन कार्रवाइयों का उल्लेख हो, बोर्ड द्वारा जारी की जा सकेगी (उन मामलों को छोड़कर जिनका उल्लेख अध्याय-VII के तहत किया गया है), ताकि नोटिसी को, निपटारे की सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह कलेंडर दिनों के भीतर, अध्याय-II के तहत निपटारे का आवेदन दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

(2) निपटारे की सूचना (नोटिस) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पास नोटिसी के खिलाफ शुरू की जाने वाली प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई के स्वरूप में परिवर्तन करने की शक्ति होगी और सूचना (नोटिस) में उल्लिखित आरोप उपरोक्त आधार पर निपटारे की मांग का या परिवर्तित आरोपों की वजह से की जाने वाली किसी प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई से बचने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगे।

(3) जहाँ नोटिसी, विनियम 15 के तहत पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल का निर्णय सूचित किए जाने से पहले किसी भी समय इस अध्याय के तहत निपटारे का आवेदन दाखिल न करता हो या निपटारे का आवेदन वापस ले लेता हो, वहाँ निर्धारित कार्यवाहियाँ शुरू की जा सकेंगी और ऐसे नोटिसी को केवल उन्हीं कार्यवाहियों की बाबत निपटारे का आवेदन दाखिल करने की अनुमति होगी, जो, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी (अजूडिकेटिंग ऑफिसर) या बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियाँ पूरी हो जाने के पश्चात् न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) के समक्ष लंबित हों।

## अध्याय-IX

### गोपनीयता के साथ निपटारा

#### गोपनीयता के साथ निपटारा

**19.** (1) जो आवेदक शुरू की जाने वाली निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे के सीमित प्रयोजन हेतु गोपनीयता का फायदा देने की मांग करता हो और बदले में प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) का उल्लंघन करने के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए जाने वाले या चल रहे अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन), निरीक्षण, जाँच या लेखापरीक्षा (ऑडिट) में काफी सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हो, वह इस अध्याय की शर्तों का पालन करेगा, जिसमें शामिल हैं -

- (क) जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, जानकारी प्रकट करने के बाद से प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) का उल्लंघन न करना;
- (ख) प्रतिभूति विधियों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन की बाबत बोर्ड के अनुसार संतोषजनक रूप में उस जानकारी, उन दस्तावेजों और उस सबूत का पूरा-पूरा और सही-सही प्रकटीकरण करना और करते रहना, जो भी उसके पास हो या जिसे वह प्राप्त कर सकता हो;
- (ग) अन्वेषण, निरीक्षण, जाँच या लेखापरीक्षा (ऑडिट) और बोर्ड के समक्ष चल रही संबंधित कार्यवाहियों के दौरान पूरी तरह से, सतत रूप से और शीघ्रता से सहयोग करना; और

(घ) किसी भी प्रकार से संबंधित दस्तावेजों को न तो छिपाना, न ही उन्हें नष्ट करना, न ही उनमें हेराफेरी करना और न ही उन्हें हटाना, ताकि कथित उल्लंघन को साबित किया जा सके।

**स्पष्टीकरण.** — इस अध्याय में प्रतिभूति विधियों के उल्लंघन का आशय अनुसूची-II में उल्लिखित प्रकटीकरण (डिस्कलोजर्स) और रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में की गई चूकों से भिन्न चूकों (डिफॉल्ट) से है:

परंतु यह कि इस अध्याय के तहत किया गया आवेदन केवल अन्वेषण (इन्वेस्टीगेशन), निरीक्षण, जाँच या लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले या उनके चलने के दौरान ही किया जाएगा।

(2) इस अध्याय में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ आवेदक इस विनियम में उल्लिखित शर्तों का पालन करने में असफल रहता हो, वहाँ बोर्ड आवेदक द्वारा किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत की गई जानकारी और प्रस्तुत किए गए सबूत के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा।

(3) उप-विनियम (1) तथा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, आवेदक पर और पाबंदियाँ या शर्तें (जो भी ठीक समझे) लगा सकेगा।

(4) गोपनीयता की मांग करने के प्रयोजनार्थ, आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि आवेदन कर सकेगा, जिसमें प्रतिभूति विधियों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने के संबंध में जानकारी और सबूत प्रस्तुत करने हेतु अनुसूची-IV में यथा निर्धारित जानकारी से संबंधित सभी प्रकटीकरण किए जाएँगे।

(5) संतुष्ट हो जाने पर, बोर्ड गोपनीयता का फायदा देने का आश्वासन दे सकेगा और उसके बाद आवेदन का वरीयता-क्रम निर्धारित कर देगा और आवेदक को इसकी सूचना लिखित में दे देगा।

(6) बोर्ड, उन कारणों से जो लिखित रूप में दर्ज किए जाएँ, किसी भी स्तर पर, आवेदन को नामंजूर कर सकेगा, यदि आवेदक के अनुसार जानकारी, दस्तावेज या सबूत अधूरे हों या झूठे हों।

(7) गोपनीयता के लिए किए गए आवेदन को नामंजूर किए जाने की सूचना आवेदक को दी जाएगी।

### प्रक्रिया

**20.** (1) इन विनियमों के अध्याय-IV से VI के प्रावधान इस अध्याय के तहत दाखिल किए गए निपटारे के आवेदन के प्रति, *यथावश्यक परिवर्तन सहित*, लागू हो सकेंगे और तदनुसार निपटारे का आदेश पारित किया जा सकेगा।

(2) इस अध्याय के तहत आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी, दस्तावेज और सबूत उसी प्रकार प्रस्तुत किए जाएँगे, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।

### गोपनीयता और आश्वासन

**21.** यदि बोर्ड को पूरा विश्वास हो कि उसे प्रदान की गई जानकारी प्रतिभूति विधि के हुए, हो रहे या होने वाले संभावित उल्लंघन से संबंधित है, तो बोर्ड आवेदक को कुछ समय के लिए गोपनीयता और आश्वासन (कि उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी) प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ विनियामक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकेगा।

### गोपनीयता

**22.** अध्याय-X में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित को गोपनीय माना जाएगा,-

(क) गोपनीयता की मांग करने वाले आवेदक की पहचान; और

(ख) आवेदक द्वारा इस अध्याय के तहत प्रस्तुत की गई जानकारी, दस्तावेज और सबूत:

परंतु यह कि, आवेदक की पहचान अथवा ऐसी जानकारी या दस्तावेज या सबूत को गोपनीय नहीं माना जा सकेगा, यदि, -

- (i) कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स) जरूरी हो;
- (ii) आवेदक ने लिखित रूप में ऐसे प्रकटीकरण के लिए सहमति दे दी हो; या
- (iii) आवेदक द्वारा सार्वजनिक तौर पर कोई प्रकटीकरण किया गया हो।

## अध्याय-X

### निपटारे के आदेश

#### न्यायनिर्णायक अधिकारी (अजूडिकेटिंग ऑफिसर) और बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों का निपटारा

**23.** (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, समुचित आदेश के माध्यम से, निपटारे की मंजूर शर्तों आदि के आधार पर, उसके समक्ष लंबित कार्यवाही का निपटारा करेगा।

*स्पष्टीकरण.* - एक साथ चल रही कार्यवाहियों के मामले में, पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया जा सकेगा और उसके बाद संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी, निपटारे के मद्देनज़र, उसके समक्ष चल रही संबंधित कार्यवाहियों का निपटारा करते हुए आदेश पारित कर सकेगा।

(2) पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल, समुचित आदेश के माध्यम से, उप-विनियम (1) में उल्लिखित कार्यवाहियों से भिन्न, शुरू की गई या शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों का निपटारा करेगा।

(3) इन विनियमों के तहत पारित किए जाने वाले निपटारे के आदेश में, कथित चूक (चूकों) के व्यौरे, प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के संबंधित प्रावधान, संक्षेप में कथित चूक से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियाँ, आवेदक द्वारा की गई स्वीकृतियाँ (यदि कोई हों) और निपटारे की शर्तें आदि शामिल होंगी।

#### न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों का निपटारा

**24.** (1) इन विनियमों में अन्यथा जो प्रावधान हैं, उसके सिवाय, निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे संबंधी प्रावधान, *यथावश्यक परिवर्तन सहित*, न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही के निपटारे के आवेदन के प्रति लागू होंगे।

(2) निपटारे की शर्तों आदि सहित निपटारे का प्रस्ताव या उसकी नामंजूरी को समुचित आदेशों के लिए ऐसे न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

#### निपटारे के आदेश की तामील और उसका प्रसार

**25.** निपटारे के आदेशों की तामील आवेदक को की जाएगी और जिन्हें बोर्ड के वेबसाइट पर भी डलवाया जाएगा:

परंतु यह कि गोपनीयता से संबंधित मामलों में निपटारे के आदेश, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, आवेदक की पहचान जाहिर (प्रकट) नहीं करेंगे, किंतु उनमें प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के उन प्रावधानों का उल्लेख होगा जिनके उल्लंघन का आरोप आवेदक पर हो।

## निपटारे की स्कीमें

**26.** इन विनियमों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड निपटारे की स्कीम के तहत, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों (जो एक ही जैसी किन्हीं निर्धारित चूकों में शामिल हों) के लिए, निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे की प्रक्रिया और निपटारे की शर्तें आदि निर्धारित कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण.** — निपटारे की स्कीम के तहत जारी किए जाने वाले निपटारे के आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तहत जारी किया गया निपटारे का आदेश है

## तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) के अधिकारों या अन्य कार्यवाहियों पर निपटारे के आदेश का प्रभाव

**27.** (1) इन विनियमों के तहत निपटारे का आदेश, न तो निपटारे के आदेश के तहत शामिल न की गई कथित चूक से संबंधित किसी अन्य कार्यवाही में सबूत के रूप में स्वीकार्य होगा और न ही वह कथित चूक की वजह से तृतीय पक्षकारों के अधिकार को प्रभावित करेगा।

(2) जहाँ कोई आवेदक, जो निपटारे का आदेश प्राप्त करता हो, किसी सिविल और प्रशासनिक कार्यवाही में किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी नोटिसी हो, वहाँ न्यायनिर्णायक अधिकारी या बोर्ड, ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाहियों का निपटारा करते समय, आवेदक के संबंध में आवश्यक टिप्पणियाँ जारी कर सकेगा, जहाँ तक वे अन्य व्यक्ति ने जो किया है उसे साबित करने के लिए आवश्यक हों:

परंतु यह कि, जब तक निपटारे का आदेश को रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक ऐसी टिप्पणियों का आवेदक पर क्या असर पड़ेगा यह आवेदक द्वारा प्राप्त किए गए निपटारे के आदेश पर निर्भर करेगा।

(3) जहाँ किसी व्यक्ति को निपटारे का ऐसा आदेश प्राप्त हुआ हो, जिसमें कथित चूक (डिफॉल्ट) करने हेतु किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में टिप्पणियाँ जारी की गई हों, ऐसा आदेश किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।

## निपटारे का आदेश रद्द करना

**28.** (1) यदि आवेदक निपटारे के आदेश का पालन करने में असफल रहता हो अथवा निपटारे का आदेश पारित होने के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड की जानकारी में यह बात आती हो कि आवेदक ने पूरा-पूरा और सही-सही प्रकटीकरण नहीं किया है अथवा वचनों या अधित्यजनों (वेवर) का उल्लंघन किया है, तो निपटारे का आदेश रद्द किया गया या वापस लिया गया माना जाएगा और बोर्ड उन कार्यवाहियों को शुरू करेगा या फिर से शुरू करेगा, जिनकी बाबत निपटारे का आदेश पारित किया जा चुका हो।

(2) जब कभी भी निपटारे का कोई आदेश रद्द कर दिया जाता हो, तो इन विनियमों के तहत अदा की गई कोई भी रकम लौटाई नहीं जाएगी।

## अध्याय-XI

### विविध

## जानकारी की गोपनीयता

**29.** (1) इन विनियमों के तहत निपटारे की कार्यवाहियों के अनुसरण में प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी और की गई चर्चाओं के बारे में यह समझा जाएगा कि वे वैश्वासीक हैसियत में प्राप्त की गई है या की गई हैं, और जो सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, यदि ऐसा करने से बोर्ड और / या आवेदक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(2) जहाँ आवेदन नामंजूर कर दिया जाए या वापस ले लिया जाए, वहाँ आवेदक और बोर्ड इन विनियमों के तहत आवेदक द्वारा किए गए किन्हीं प्रस्तावों या प्रस्तुत की गई किसी जानकारी या आवेदक की ओर से रखे गए पक्ष पर, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष, न तो निर्भर रहेंगे और न ही उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे:



परंतु यह कि यह उप-विनियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ निपटारे का आदेश इन विनियमों के तहत रद्द कर दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो।

**स्पष्टीकरण.** – जब आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त होने के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता हो, तो ऐसी जानकारी, चाहे वह स्वीकृत की गई हो या स्वीकृत न की गई हो, साबित की जा सकेगी जो सामने आए तथ्य से काफी हद तक संबंधित हो।

### **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**

**30.** इन विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या या उनके लागू होने आदि में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, बोर्ड के पास परिपत्रों (सर्कुलर्स) या दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) के जरिए स्पष्टीकरण जारी करने और प्रक्रियाएँ निर्धारित करने की शक्ति होगी।

### **प्रक्रिया में अनियमितता**

**31.** निपटारे का कोई भी आदेश या निपटारे के आवेदन की कोई भी नामंजूरी, प्रक्रिया में या निपटारे की रकम की गणना में किसी खामी के आधार पर अथवा अध्याय-V के तहत किसी समिति में कोई पद खाली रहने पर या उस समिति के गठन में किसी खामी के आधार पर शून्य हो जाएगी:

परंतु यह कि, इन विनियमों की कोई भी बात बोर्ड को निपटारे का आदेश वापस लेने से नहीं रोकेगी जहाँ आवेदक निपटारे की रकम की गणना में कोई विसंगति होने की वजह से उतनी रकम अदा करने में असफल रहता हो जितनी रकम का अंतर पाया जाए:

परंतु यह और कि, आवेदक उन अधित्यजनों (वेवर) का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा, जो कोई कानूनी कार्यवाही शुरू किए जाने या जारी रखने या दोबारा शुरू करने के संबंध में प्रस्तुत किए गए हों और जो अनुसूची-I के भाग-ग में यथा उल्लिखित वचन तथा अधित्यजन के पैरा 12 के उप-पैरा (घ), (ङ), (च) तथा (छ) में प्रस्तुत किए गए हों।

### **निर्धारित कार्यवाहियों में इन विनियमों की प्रासंगिकता**

**32.** इन विनियमों की अनुसूची-II प्रासंगिक होगी, किंतु जो किसी निर्धारित कार्यवाही में बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं होगी और बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी उन्हें यथासंभव रूप में लागू कर सकेगा।

### **शमन की प्रक्रिया**

**33.** अनुसूची-II के अध्याय-IV से VI के प्रावधान शमन के आवेदन के अनुसरण में किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के संबंध में *यथावश्यक परिवर्तन सहित* लागू हो सकेंगे।

### **निरसन और व्यावृत्तियाँ**

**34.** (1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसा कोई निरसन हो जाने पर भी:

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 के तहत जारी की गई निपटारे की सूचना (नोटिस) के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के अनुसार दाखिल की गई है और उनके संबंध में इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 के तहत दाखिल किए गए और बोर्ड के पास लंबित सभी आवेदनों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इन विनियमों के अनुसार दाखिल किए गए हैं और उनके संबंध में इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 के तहत पारित किए गए निपटारे के सभी आदेशों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इन विनियमों के तहत पारित किए गए हैं;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित आंतरिक समिति (समितियों) तथा उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इन विनियमों के तहत गठित की गई हैं;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 के अनुसार आंतरिक समितियों के प्रस्तावों तथा उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिशों और इन सिफारिशों के आधार पर बोर्ड द्वारा की गई किसी कार्रवाई के बारे में यह समझा जाएगा कि ऐसा इन विनियमों के तहत किया गया है।

(3) अध्याय-VI से अध्याय-VIII में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख तक लंबित निर्धारित कार्यवाहियों के संबंध में, बोर्ड ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में अध्याय-VII या अध्याय-VIII के तहत, यथास्थिति, संक्षिप्त निपटारे की सूचना या निपटारे की सूचना जारी कर सकेगा और ऐसे मामलों में, यथास्थिति, अध्याय-VII या अध्याय-VIII में निर्धारित प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होगी।

**स्पष्टीकरण** - इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित कार्यवाही तब तक शुरू की गई या लंबित नहीं समझी जाती, जब तक कि बोर्ड उस प्राधिकरण के पास यह मामला भिजवा न दे, जो ऐसी कार्यवाहियाँ चलाएगा।

**अनुसूची-I**

(विनियम 3 देखें)

**भाग-क****फॉर्म****निपटारे के लिए आवेदन**

**[यथास्थिति अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन), निरीक्षण, जाँच या लेखापरीक्षा (ऑडिट) पूरी हो जाने के बाद ही भरा जाए]**

(केवल कार्यालय के उपयोग के लिए)

आवेदन प्राप्त होने की तारीख :

आवेदन की रजिस्ट्रीकरण संख्या :

**[अनुदेश:** सभी विवरण (जिनमें शामिल हैं - निवेशकों को हुई हानि, कमाए गए मुनाफे और निपटारे की प्रस्तावित रकम के व्यौरों के संबंध में अपना पक्ष) **अवश्य** भरे जाएँ, नहीं तो आवेदन लौटा दिया जाएगा। जहाँ लागू न हो, वहाँ केवल 'लागू नहीं' लिखें।]

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के समक्ष**

..... के मामले में

1. आवेदक / सह-आवेदकों का नाम / ट्रेड नाम :
  - (क) रजिस्ट्रीकरण सं., यदि लागू हो :
  - (ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख, यदि लागू हो :
  - (ग) पैन / डीआईएन / सीआईएन संख्या (जो भी उपलब्ध हो) :
  - (घ) आवेदक की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) :
2. स्टॉक दलाल होने के मामले में स्टॉक एक्सचेंज का नाम :
3. उप-दलाल (सब-ब्रोकर) / प्राधिकृत व्यक्ति होने के मामले में उस स्टॉक दलाल का नाम जिसके साथ जुड़े हुए हों और स्टॉक एक्सचेंज का नाम :
4. खंड (सेगमेंट) का नाम [नकदी (कैश) / व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव), आदि]:
5. संगठन का स्वरूप : निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) / एकमात्र स्वत्वधारी (सोल प्रोप्राइटरशिप) / भागीदारी (पार्टनरशिप) / एलएलपी / वित्तीय संस्था [यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी हो, तो सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के व्यौरे] :
6. संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) / निदेशकों / स्वत्वधारियों (प्रोप्राइटर्स) / भागीदारों के नाम :
7. प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति :
8. पता / पत्र-व्यवहार का पता, संपर्क सं. / फैक्स सं. तथा ई-मेल (उपरोक्त व्यौरों में होने वाले किसी बदलाव की सूचना बोर्ड को जल्द से जल्द दी जाएगी) :
9. संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) का (के) नाम तथा उसके (उनके) संपर्क संबंधी व्यौरे (ई-मेल सहित) :
10. बोर्ड से अन्य रजिस्ट्रीकरण, यदि लागू हो :
  - (क) ट्रेड नाम :
  - (ख) रजिस्ट्रीकरण का प्रकार :
  - (ग) रजिस्ट्रीकरण सं. :

11. बोर्ड / प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) / न्यायालय के पास लंबित मामला (मामले) (कृपया उल्लेख करें) :
12. 11ख (11बी) / न्यायनिर्णयन (अड्जूडिकेशन) / जाँच / अन्यो से संबंधित लंबित मामला (मामले) (कृपया उल्लेख करें) :
13. किस चरण पर लंबित है (हैं) :
14. लंबित कार्यवाहियों के संबंध में अंतरिम आदेश (इंटरिम ऑर्डर) [पारित किए गए आदेशों का सार], यदि कोई हो (हों) :
15. बोर्ड के पास लंबित / बोर्ड द्वारा पूरी की गई अन्य कार्रवाइयाँ, यदि कोई हों (उनके व्यौरों सहित) :
  - (क) आवेदक के खिलाफ :
  - (ख) उसके सहयोगियों के खिलाफ :
  - (ग) उसके प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ :
  - (घ) उसके अन्य संप्रवर्तकों (प्रमोटर्स) / निदेशकों के खिलाफ :
  - (ङ) अन्य व्यौरे, यदि कोई हों :
16. उस कारण बताओ सूचना (इन्फॉर्मेशन) / समन / सूचना की तारीख, जिसमें उस संभावित वाद हेतुक, यदि कोई हो, का उल्लेख हो, जिसकी बाबत निपटारे की मांग की गई हो (कृपया प्रतियाँ संलग्न करें) :
17. तथ्यों का पूरा-पूरा और सही-सही प्रकटीकरण [जिनमें शामिल हैं - वाद हेतुक की बाबत हुए नुकसान, कमाए गए मुनाफे, टाले गए नुकसान, सकल फीस, दलाली, कमीशन आदि (उन्हें निकालने के तरीके के साथ)] :

[आवेदक अनुसूची-II में दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखे]

18. कथित निश्चित आरोप :
19. विनियम 5 के उप-विनियम (2), (3) एवं (4) के संबंध में अपना पक्ष :
20. आवेदक द्वारा प्रस्तावित निपटारे की शर्तें आदि :-
  - (क) आर्थिक शर्तें आदि, उन्हें निकालने के तरीके के साथ :-
  - (ख) गैर-आर्थिक शर्तें आदि, जिनमें प्रत्यर्पण के लिए देयराशि की गणना का तरीका भी शामिल है :-
21. संलग्न किए जाने वाले मूल दस्तावेज :
  - (क) वचन और अधित्यजन (भाग-ग में निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार) ।
  - (ख) प्राधिकार-पत्र (अथॉरिटी लेटर) / बोर्ड का संकल्प (बोर्ड रेज़ोल्यूशन) ।
22. अन्य संलग्नकों की सूची :
  - (क) उस कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस) / समन / सूचना / अन्य सूचनाओं की प्रति, जिसमें उस संभावित वाद हेतुक, यदि कोई हो, का उल्लेख हो जिसकी बाबत निपटारे की मांग की गई हो;
  - (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों की पूर्ण वार्षिक रिपोर्टें / अन्य संबंधित वित्तीय विवरण तथा चालू वर्ष के लेखारीक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम;
  - (ग) विवरण, जिसमें आवेदक की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) [केवल उन आवेदकों के लिए जिनसे यह अपेक्षित है कि वे बोर्ड द्वारा या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा यथा निर्धारित शुद्ध-मालियत संबंधी

- अपेक्षाओं का पालन करें], कर से पूर्व सकल वार्षिक आय, कमाए गए मुनाफे / टाले गए नुकसान की सकल रकम (जिसमें शामिल है उक्त चूक की बाबत सकल दलाली, फीस, प्रबंधन/कार्य-निष्पादन/लेनदेन संबंधी फीस, आगे ले जाया गया व्याज, प्रतिकर, आदि) को दर्शाया जाए;
- (घ) पैन कार्ड की प्रति / डीआईएन/सीआईएन के ब्यौरे;
- (ङ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आवेदक की आय-कर की पूरी विवरणियाँ ;
- (च) यदि आवेदक विदेशी निगमित निकाय हो, तो निगमन, कारबार के स्थान से संबंधित ब्यौरों, किसी गैर-भारतीय वित्तीय क्षेत्र के विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) से लिए गए रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों को शामिल करें।
- (छ) यदि आवेदक अनिवासी हो, तो पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान-पत्र (नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट), यदि कोई हो, से संबंधित ब्यौरों को शामिल करें।
- (ज) कोई अन्य संबंधित दस्तावेज / पक्ष।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

[निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) आवेदक की स्टाम्प और मुहर]

### सत्यापन

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी (नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें) श्री ..... आवेदक / ..... का प्राधिकृत प्रतिनिधि [निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में] होने के नाते, एतद्वारा यह सत्यापित करता/करती हूँ और शपथ पर यह स्वीकार करता/करती हूँ कि यह आवेदन और इसमें दी गई बातें मेरी जानकारी एवं विश्वास तथा रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं और यह कि मैंने कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाए हैं और मैं ऐसी किसी अन्य संबंधित जानकारी से बोर्ड को बिना किसी देरी के अवगत कराता रहूँगा/कराती रहूँगी जो भी मुझे पता चले।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान :

### भाग-ख

इन विनियमों के अध्याय-II के तहत प्रत्येक आवेदक, 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड' के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से या बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से पंद्रह हजार रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) प्रोसेसिंग फीस अदा करेगा :

परंतु यह कि, जहाँ आवेदक निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो, वहाँ अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) प्रोसेसिंग फीस पच्चीस हजार रुपये होगी।

**भाग-ग****वचन और अधित्यजन****फॉर्मेट**

प्रत्येक आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला वचन विधिवत् रूप से स्टाम्प शुल्क अदा करके और विधिवत् रूप से नोटरी करवाकर प्रस्तुत किया जाए।

मैं / हम, ..... (आवेदक), आवेदन को जाँचने और आवेदन पर विचार करने के लिए बोर्ड के पास संलग्न आवेदन करने की शर्त के रूप में, एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि मैं / हम सहमत हूँ / हैं और यह वचन देता/देती हूँ / देते हैं कि :

- (1) मैं / हम कथित चूक के संबंध में समुचित कार्यवाहियाँ शुरू करने के भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के क्षेत्राधिकार और अधिकार को स्वीकारता/स्वीकारती हूँ / स्वीकारते हैं।
- (2) मैं / हम इस बात से भी सहमत हूँ / हैं और यह वचन देता/देती हूँ / देते हैं कि निपटारे की कार्यवाहियों के दौरान लगे समय पर, मेरे / हमारे खिलाफ, किन्हीं कानूनी कार्यवाहियों, यदि कोई हों, को शुरू करने या जारी रखने या दोबारा शुरू करने के संबंध में परिसीमा (लिमिटेशन) की अवधि या अतिविलंब (लैचिज़), यदि कोई हों, की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किन्हीं आपत्तियों को अधित्यजित (वेव) करता/करती हूँ / करते हैं।
- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड इस आवेदन के अनुसरण में पारित किए गए निपटारे के आदेश के किसी उल्लंघन के संबंध में या की वजह से मेरे / हमारे खिलाफ उठने वाले किन्हीं दावों की बाबत कार्रवाई कर सकेगा।
- (4) निपटारे के आदेश की कोई भी बात किसी अन्य व्यक्ति को कोई अन्य कानूनी उपाय (जो कानून के अनुसार ऐसा व्यक्ति मेरे / हमारे खिलाफ करने का हकदार हो) करने से नहीं रोकेगी।
- (5) मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तावित निपटारा किसी व्यक्ति के लिए, जो इन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं है, मेरे / हमारे खिलाफ प्रयोग किए जा सकने वाले किन्हीं निजी अधिकारों या उपचारों को सीमित या सृजित नहीं करता है।
- (6) निपटारे की रकम, जिसमें कानूनी खर्चे (यदि कोई हों) शामिल हैं, बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर मेरे / हमारे द्वारा बोर्ड को अदा की जाएगी।
- (7) निपटारे के आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार है और वह तदनुसार लागू किया जाएगा।
- (8) मैं / हम सहमत हूँ / हैं कि निपटारे का आदेश पारित होने के पश्चात्, मैं / हम, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, बोर्ड के किसी निष्कर्ष (जिसके अंतर्गत निपटारे के आदेश में रिकॉर्ड किया गया निष्कर्ष शामिल है) से

इनकार करते हुए या यह धारणा बनाते हुए कि निपटारे का आदेश तथ्यों के आधार पर नहीं है, कोई कार्यवाई नहीं करूँगा/करूँगी / करेंगे या सार्वजनिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं करूँगा/करूँगी / करेंगे या ऐसा किए जाने की अनुमति नहीं दूँगा/दूँगी / देंगे ।

- (9) मैं / हम एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए अधित्यजनों (वेवर) और वचन की कोई भी बात (i) मेरी / हमारी गवाही देने संबंधी बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगी या (ii) मेरे / हमारे उस अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जिसके तहत मैं / हम उस मुकदमे के पक्ष में अथवा दावे के पक्ष में या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही, जिसमें बोर्ड पक्षकार न हो, के पक्ष में किसी कानून का या तथ्यों का आधार ले सकता हूँ / ले सकते हैं ।

- (10) मैं / हम इन विनियमों के तहत निपटारे के सीमित प्रयोजन से 'तथ्य के निष्कर्षों और विधि के निष्कर्षों को स्वीकारता/स्वीकारती हूँ / स्वीकारते हैं' या 'न तो तथ्य के निष्कर्षों और विधि के निष्कर्षों को स्वीकारता/स्वीकारती हूँ / स्वीकारते हैं और न ही इनसे इनकार करता/करती हूँ / करते हैं' (जो भी लागू न हो उसे काट दें), और इस संबंध में निपटारे के आदेश [जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 पारित किया जाए] तथा बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) एवं परिपत्रों (सर्कुलर) का पालन करने के लिए सहमत हूँ / हैं :

परंतु यह कि, प्रॉस्पेक्टस या प्रस्ताव-पत्र या ऐसे ही दस्तावेजों में किए जाने वाले प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र) [जो प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यू) के संबंध में किए जाने जरूरी हों] से भिन्न प्रकटीकरणों से संबंधित चूकों के संबंध में, मैं / हम कथित चूक से इनकार नहीं करता/करती हूँ / करते हैं ।

- (11) मैं / हम निपटारे के आदेश (जिसे पारित किया जा सकता है) में निहित किसी मुद्दे के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाहियाँ करने के अपने अधिकार का त्याग करता/करती हूँ / करते हैं ।

- (12) मैं / हम :

(क) तथ्यों के निष्कर्षों और विधि के निष्कर्षों का;

(ख) बोर्ड या बोर्ड के किसी अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों का;

(ग) सुनवाई के बाद की समस्त प्रक्रियाओं संबंधी अधिकार का;

(घ) न्यायाधिकरण / न्यायालयों के समक्ष अपील / समीक्षा का;

(ङ) विनियमों के ऐसे प्रावधानों या अन्य कानूनी अपेक्षाओं (जिसमें हित-विरोध भी शामिल है) से संबंधित किसी अर्जी का, जिनका अर्थ यह लगाया जा सकता हो कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को कार्यवाहियों (जिनमें निपटारे की कार्यवाहियाँ शामिल हैं) में शामिल होने से अथवा किसी आदेश, राय, तथ्य के निष्कर्ष, या विधि के निष्कर्ष के संबंध में, आंतरिक समिति, उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल की सहायता करने या को सुझाव आदि देने से रोकती है;

- (च) समस्त आंतरिक कार्यवाहियों या उनके किसी भाग के निपटारे पर विचार करने के या से संबंधित चर्चाओं के आधार पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, अधिकारियों या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के पक्षपातपूर्ण निर्णय या पूर्व-निर्णय के संबंध में दी गई किसी अर्जी का;
- (छ) यदि आवेदक निपटारे के आदेश का उल्लंघन करता हो, तो कार्यवाहियों को शुरू करने या दोबारा शुरू करने के संबंध में परिसीमा (लिमिटेशन) या अतिविलंब (लैचिज़) से संबंधित किसी अर्जी का भी त्याग करता/करती हूँ / करते हैं।

- (13) मैं / हम निपटारे की शर्त के रूप में यह वचन देता/देती हूँ / देते हैं कि मैं / हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी सेट-ऑफ, क्षतिपूर्ति, बीमा कवर के जरिए किसी प्रतिपूर्ति या कर से भिन्न किसी दूसरी प्रतिपूर्ति की माँग नहीं करूँगा/करूँगी / करेंगे।

[आवेदक के हस्ताक्षर - निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) की स्टाम्प और मुहर के साथ]

मेरे समक्ष

नोटरी

### अनुसूची-II

(विनियम 10 देखें)

#### अध्याय-I

#### निपटारे की शर्तें आदि तय करने हेतु दिशानिर्देश

1. निपटारे की रकम (सेटलमेंट अमाउंट या एसए) में इन दिशानिर्देशों और विनियम 10 में दिए गए कारकों (जहाँ कहीं भी लागू हों) के अनुसार तय की गई सूचक राशि (इंडिकेटिव अमाउंट या आईए) शामिल है।
2. सूचक राशि (आईए), यथास्थिति, पहली बार आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए 3 लाख रुपये से या अन्यो के लिए 7 लाख रुपये से कम नहीं होगी :

परंतु यह कि जो व्यक्तिगत आवेदक आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के अनुसार संतोषजनक रूप में यह वचन प्रस्तुत करते हों कि गैर-कानूनी क्रियाकलाप की जानकारी के बिना ही उन्होंने प्रतिभूतियों संबंधी अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति ऐसे क्रियाकलाप से जुड़े की-ऑपरेटर या मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या प्रतिभूति बाजार की बुनियादी संस्था को दे दी थी, उन आवेदकों के मामले में निपटारे की रकम प्रतिभूति विधियों के तहत ऐसे उल्लंघन के लिए निर्धारित न्यूनतम शास्ति (पेनल्टी) से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण.** - 'पहली बार आवेदन करने वाला आवेदक' वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ न्यायनिर्णायक अधिकारी (अड्जुडिकेटिंग ऑफिसर) द्वारा या बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित न किया गया हो अथवा जिसने वर्तमान आवेदन की तारीख तक बोर्ड की ओर से कभी भी निपटारे का आदेश प्राप्त न किया हो।

3. जिस कार्यवाही (जिन कार्यवाहियों) के लिए आवेदन किया गया हो, वह कार्यवाही (वे कार्यवाहियाँ) जिस चरण पर लंबित हो (हों), उसके आधार पर ही, सूचक राशि (आईए) की गणना करते समय प्रोसीडिंग कन्वर्जन फैक्टर (पीसीएफ) लगाया जाएगा।



4. उन मामलों में, जहाँ किसी व्यक्ति का मौजूदा कारबार या क्रियाकलाप सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) या भागीदारी में या तो निगमित या परिवर्तित हो चुका हो अथवा किसी नए प्रबंध-मंडल द्वारा उसका विलय या अधिग्रहण कर लिया गया हो, वहाँ पहले की एंटीटी के मौजूदा रिकॉर्ड को नई एंटीटी का रिकॉर्ड समझा जाएगा। विचार करने योग्य बातों जैसे दिवालियापन, नाम या प्रबंध-मंडल या स्वामित्व में परिवर्तन, आदि पर विचार बोर्ड द्वारा समय-समय जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार किया जाएगा।
5. स्वेच्छा से किए जाने वाले या गोपनीयता की मांग करते हुए किए जाने वाले आवेदनों हेतु पीसीएफ : जहाँ एंटीटी कम पीसीएफ का लाभ पाने की इच्छुक हो, वहाँ वह, *स्वप्रेरणा से*, कोई कारण बताओ सूचना (नोटिस) प्राप्त होने से पूर्व, बोर्ड को ऐसी चूक की जानकारी दे सकेगी [यहाँ आगे 'चूक संबंधी सूचना (इन्टीमेशन डिफॉल्ट)' के रूप में उल्लिखित] और बोर्ड को अन्वेषण, जाँच, निरीक्षण या लेखापरीक्षा (ऑडिट) में सहयोग कर सकेगी। पीसीएफ की गणना करने के प्रयोजनार्थ, ऐसे आवेदन के बारे में यह समझा जाएगा कि यह आवेदन 'कारण बताओ सूचना (नोटिस) जारी होने से पहले' किया गया है।
6. इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सूचक राशि (आईए) की गणना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हर चूक की बाबत (संयुक्त रूप से या अलग-अलग) की जाएगी।
7. आवेदन पर विचार करते समय, निरीक्षण रिपोर्ट या अन्वेषण रिपोर्ट या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (डीए) की रिपोर्ट या किसी लंबित कार्यवाही के दौरान किसी प्राधिकारी द्वारा जारी की गई कारण बताओ सूचना, जिसमें कारण बताओ सूचना के बाद जारी की जाने वाली सूचना भी शामिल है, में उल्लिखित कथित चूक (चूकें), अथवा नामनिर्दिष्ट सदस्य (डिसिग्रेटेड मेंबर / डीएम) या पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) या न्यायनिर्णायक अधिकारी (एओ) या प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट), जो भी लागू हो, के आदेश में उल्लिखित तथ्य / निष्कर्ष सूचक राशि (आईए) की गणना के आधार हो सकेंगे।  
यदि, आंतरिक समिति (आईसी) या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (एचपीएसी) या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल की यह राय हो कि तथ्य किसी भिन्न चूक को प्रकट (जाहिर) करते हैं, तो आरोप (आरोपों) में बदलाव की मांग की जा सकेगी।
8. कथित चूकों का वर्गीकरण, जहां कहीं भी लागू हो, आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।
9. इन दिशानिर्देशों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के पास विवेकाधिकार होगा जिसके तहत वह प्रतिभूति विधियों के प्रावधानों के अनुसार, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए, उन कारणों से जो दर्ज किए जाएं, आवेदन को स्वीकार या नामंजूर किए जाने की सिफारिश कर सकेगा अथवा उसे स्वीकार या नामंजूर कर सकेगा, इन दिशानिर्देशों के अनुसार तय की गई रकम से कम या अधिक रकम की सिफारिश कर सकेगा।
10. यदि आवेदक निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो, तो आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल यह अपेक्षा कर सकेगा कि निगमित निकाय द्वारा अदा की जाने वाली निपटारे की रकम चूककर्ता अधिकारियों (जिनमें निगमित निकाय के प्रभारी व्यक्ति भी शामिल हैं) द्वारा अदा की जाए, ताकि उस निगमित निकाय द्वारा निर्गमित (जारी / इश्यू की गई) प्रतिभूतियों को धारण करने वाले निवेशकों पर बोझ न पड़े।

**स्पष्टीकरण.** - खंड 10 में दिया गया सिद्धांत, *यथावश्यक परिवर्तन सहित*, यथास्थिति, प्रायोजक, प्रबंधक, या न्यास के न्यासी (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए), हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता, व्यक्तियों के संघ (असोसिएशन) के पदाधिकारियों के प्रति लागू हो सकेगा।

11. ऐसे मामलों में जहाँ सूचक राशि (आईए) की गणना करने के फार्मूले लागू न होते हों अथवा चूक के विशेष स्वरूप या मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की वजह से इन फार्मूलों को ढाला न जा सकता हो अथवा जहाँ इन दिशानिर्देशों में दी गई सारणियों के अंतर्गत उल्लिखित चूकें इनके दायरे में न आती हों, वहाँ आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल निपटारे की रकम तय कर सकेगा, जैसा वे ठीक समझें।
12. प्रतिभूति विधियों में संशोधन हो जाने या उनके निरसित हो जाने की दशा में, ये दिशानिर्देश, *यथावश्यक परिवर्तन सहित*, संशोधित या नई कानूनी अपेक्षाओं के तहत ऐसे प्रावधानों पर लागू रहेंगे।

### अध्याय-II

#### सूचक राशि और निपटारे की रकम

सूचक राशि (आईए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

$$\text{आईए} = \text{ए} \times \text{बी} + \text{कानूनी खर्चे}\#$$

#बोर्ड द्वारा किए गए कानूनी खर्चे सारणी-I में यथा उल्लिखित क्रम "ख", "घ" एवं "ङ" के अंतर्गत उल्लिखित चरणों के दौरान किए गए आवेदन पर लागू हो सकेंगे।

जहाँ:

**'ए'** = पीसीएफ + आरएएफ

**ए** : गुणन कारक (मल्टीप्लाइंग फैक्टर)

**पीसीएफ** : प्रोसीडिंग कन्वर्ज़न फैक्टर

**आरएएफ** : विनियामक कार्रवाई संबंधी कारक (रेग्युलेटरी एक्शन फैक्टर)

**'बी'** = बीवी x बीए

**'बी'** : लागू बेंचमार्क राशि, वह राशि है जो इन दिशानिर्देशों के अनुसार हर कथित चूक से संबंधित है;

**'बीवी'** : किसी विशेष आरोप के संबंध में उसकी गंभीरता को बढ़ाने वाले तथा कम करने वाले संबंधित कारकों को दिए गए आधार मान (बेस वैल्यू) का जोड़

**'बीए'** : इन दिशानिर्देशों के अनुसार हर कथित चूक के संबंध में आधार राशि (बेस अमाउंट)

1. सूचक राशि (आईए) उस अधिकतम शास्ति (पेनल्टी) से ज्यादा नहीं होगी, जो प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के तहत प्रत्येक उल्लंघन के लिए लगाई जा सकती हो और उसे इन विनियमों के अनुसार की गई कथित चूकों की संख्या से गुणा किया जाएगा।
2. (क) जहाँ शास्ति (पेनल्टी) का आदेश आवेदन करने के पहले पारित कर दिया गया हो, वहाँ 'बी' इस प्रकार लगाई गई शास्ति (पेनल्टी) से कम नहीं होगा;  
(ख) यदि उसी वाद हेतुक (कॉज ऑफ़ एक्शन) की बाबत एक से अधिक कार्यवाहियाँ आवेदक के खिलाफ शुरू की गई हों, तो सूचक राशि (आईए) में 20% तक की वृद्धि हो जाएगी।
3. गोपनीयता प्रदान किए जाने के मामले में, इस अनुसूची के अनुसार तय की गई सूचक राशि (आईए) में निम्नानुसार घटाई जा सकेगी,-
  - i. वरीयता-क्रम में जिनका पहला स्थान हो, उनके संबंध में सूचक राशि (आईए) नब्बे प्रतिशत तक या उसके बराबर घटाई जा सकेगी;
  - ii. वरीयता-क्रम में जिनका दूसरा स्थान हो, उनके संबंध में सूचक राशि (आईए) पचास प्रतिशत तक या उसके बराबर घटाई जा सकेगी; और
  - iii. वरीयता-क्रम में जिनका तीसरा स्थान हो या उसके बाद के स्थान हो, उनके संबंध में सूचक राशि (आईए) पच्चीस प्रतिशत तक या उसके बराबर घटाई जा सकेगी।
4. पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा अंतिम रूप से मंजूर की गई रकम **निपटारे की रकम** (एसए) होगी।
5. इस अनुसूची में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, -
  - i. जहाँ प्रतिभूति विधियों के तहत शास्ति (पेनल्टी) का भुगतान न करने के अपराध की बाबत शमन किए जाने हेतु आवेदन दाखिल किया गया हो, वहाँ न्यायालय के समक्ष अपराध के शमन से सहमत होने संबंधी प्रस्ताव, ऐसी शास्ति और व्याज (जो उचित समझा जाए) के साथ-साथ कानूनी खर्चों (जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएँ) के बदले, दिया जा सकेगा;
  - ii. जहाँ प्रतिभूति विधियों के तहत शास्ति (पेनल्टी) का भुगतान न करने के अपराध से भिन्न किसी अपराध की बाबत शमन किए जाने हेतु आवेदन दाखिल किया गया हो, वहाँ न्यायालय के समक्ष अपराध के शमन से सहमत होने संबंधी प्रस्ताव, ऐसी शर्तों आदि के बदले दिया जा सकेगा जो पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा मंजूर की जाएँ; और
  - iii. जहाँ न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने के पश्चात् शमन किए जाने हेतु आवेदन दाखिल किया जाता हो, वहाँ शमन से सहमत होने संबंधी प्रस्ताव तभी दिया जा सकेगा, जब इस अनुसूची के तहत निकाली की गई राशि को कम से कम पच्चीस तक बढ़ाने के साथ-साथ उसमें कानूनी खर्च भी जोड़ दिए जाएँ और साथ ही अन्य शर्तों आदि (जैसी पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा मंजूर की जाएँ) भी लगाई जा सकेंगी।

### अध्याय-III

#### **प्रोसीडिंग कन्वर्ज़न फैक्टर (पीसीएफ)**

आवेदन की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, कार्यवाहियों के चरण के आधार पर नियत मान, सारणी-1 के अनुसार पीसीएफ होंगे:

परंतु यह कि जहाँ उसी वाद हेतुक (कॉज़ ऑफ़ एक्शन) की वजह से चलने वाली एक से अधिक कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने की मांग की जाए, वहाँ, अन्य कार्यवाहियों की प्रगति के बाद उनके चरण पर विचार किए बिना, उस कार्यवाही, जो सबसे अग्रिम चरण में हो, के मान को पीसीएफ के रूप में लिया जाएगा।

#### **सारणी-I**

#### **पीसीएफ**

<b>निपटारे का आवेदन किए जाने के समय कार्यवाही (कार्यवाहियों) की अवस्था</b>		<b>पीसीएफ का मान (वैल्यू)</b>
<b>क.</b>	स्वेच्छा से या गोपनीयता की मांग करते हुए निपटारे के लिए	0.65
<b>ख.</b>	कारण बताओ सूचना (नोटिस) जारी होने से पहले [जिसमें निपटारे की सूचना (नोटिस)/संक्षिप्त निपटारे की सूचना (नोटिस) प्राप्त होने पर दाखिल किए गए आवेदन शामिल हैं] [अथवा समन से पूर्व शमन हेतु दाखिल किया गया आवेदन]	0.75
<b>ग.</b>	उसी वाद हेतुक (कॉज़ ऑफ़ एक्शन) में किसी लंबित कार्यवाही के संबंध में पहली कारण बताओ सूचना (नोटिस) जारी होने के पश्चात् [जिसमें निपटारे की सूचना (नोटिस) में दी हुई अवधि के पश्चात् दाखिल किए गए आवेदन शामिल हैं] [अथवा आरोप तय होने से पहले शमन हेतु दाखिल किया गया आवेदन]	0.85
<b>घ.</b>	नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् लंबित कार्यवाही [अथवा आरोप तय होने के बाद शमन हेतु दाखिल किया गया आवेदन]	0.9
<b>ङ.</b>	अंतिम आदेश [जिसके माध्यम से, यथास्थिति, शास्ति लगाई गई हो या सिविल और प्रशासनिक निदेश जारी किए गए हों] पारित किए जाने के पश्चात् लंबित कार्यवाहियाँ	1.10
<b>च.</b>	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) या न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् लंबित कार्यवाहियाँ	1.20

#### **अध्याय-IV**

#### **विनियामक कार्रवाई कारक (रेग्युलेटरी एक्शन फैक्टर) - सभी आदेशों और विनियामक निदेशों के लिए मान**

पहले कभी जारी किए गए आदेश और विनियामक निदेश (निदेशों), यदि कोई हों, के लिए नियत समस्त मानों का योग 'आरएएफ' होगा।

**'आरएएफ' = एक्स + वाई****"सारणी-II - जारी किए गए आदेशों और विनियामक निदेशों के लिए मान - एक्स"**

\* उन आदेशों और निदेशों को भी शामिल किया जाना है जिन पर, आवेदन की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) या न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। यदि उसी वाद हेतुक (काँज ऑफ एक्शन) के लिए एक से अधिक कार्यवाहियाँ शुरू की गई हों, तो पारित किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश के लिए मान जोड़ दिया जाएगा।

आवेदक को जारी किए गए आदेश और विनियामक निदेश	एक्स प्रति आदेश
जिन मामलों में बरी कर दिया गया हो (अर्थात् ऐसे मामले जहाँ आवेदक को आदेश या अपील या समीक्षा के तहत बरी कर दिया गया था) और निपटारे का कोई आदेश जिसमें गोपनीयता शामिल हो	0
निपटारे का कोई अन्य आदेश	0.01
<b>अन्य सभी आदेश (उन आदेशों को छोड़कर जिनके लिए आवेदन दाखिल किया गया है)</b>	
परिविरत (सीज़) और प्रतिविरत (डीजिस्ट) आदेश	0.02
प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जारी अंतिम आदेश	0.05
मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) या प्रतिभूति बाजार की बुनियादी संस्थाओं* अथवा सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनियों, और उनके मुख्य अधिकारियों के खिलाफ जारी अंतिम आदेश	0.075

\*इस अनुसूची में, 'मध्यवर्ती या प्रतिभूति बाजार की बुनियादी संस्थाओं' में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल है जिसके लिए प्रतिभूति विधियों के तहत यह अपेक्षित है कि वह बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत अथवा मान्यताप्राप्त हो।

**सारणी-III - पारित या जारी किए गए आदेश या निदेश, जिसके लिए आवेदन दाखिल किया गया है, के****लिए मान - वाई**

मध्यवर्ती या प्रतिभूति बाजार की बुनियादी संस्था के खिलाफ अंतिम आदेश, जिसके संबंध में आवेदन किया गया था	मध्यवर्ती या प्रतिभूति बाजार की बुनियादी संस्था से भिन्न किसी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम आदेश, जिसके संबंध में आवेदन किया गया था	'वाई' प्रति आदेश
जारी की गई चेतावनी		0.05
1 महीने तक के लिए निलंबन / विवर्जन	6 कलेंडर महीनों तक के लिए विवर्जन	0.1
1 महीने या उससे अधिक की अवधि तक के लिए किंतु 6 महीनों से कम के लिए निलंबन/विवर्जन	6 कलेंडर महीनों या उससे अधिक की अवधि तक के लिए किंतु 1 वर्ष से कम के लिए विवर्जन	0.15

6 महीने या उससे अधिक की अवधि तक के लिए किंतु 1 वर्ष से कम के लिए निलंबन / विवर्जन	1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक के लिए किंतु 2 वर्ष से कम के लिए विवर्जन	0.2
1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक के लिए किंतु 2 वर्ष से कम के लिए निलंबन / विवर्जन	2 वर्षों या उससे अधिक की अवधि तक के लिए किंतु 3 वर्ष से कम के लिए विवर्जन	0.25
2 वर्षों या उससे अधिक की अवधि तक के लिए निलंबन / विवर्जन	3 वर्षों या उससे अधिक की अवधि तक के लिए विवर्जन	0.3

### अध्याय-V

#### लागू आधार मान (बेस वैल्यू) और कारक

#### बीबी=1+लागू आधार मानों का योग

- I. संबंधित कारकों पर विचार करते समय, आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल गंभीरता को कम करने वाले निम्नलिखित सामान्य कारकों (जनरल मिटिगेटिंग फैक्टर्स) पर विचार कर सकेगा, जिसका आधार मान '-0.2' होगा जो केवल एक बार ही लगाया जाएगा फिर चाहे सभी के लिए लगाया जाए या किसी एक या एक से अधिक के लिए लगाया जाए:
  1. सूचक राशि (आईए) की मात्रा आवेदक की निवेशकों को पैसा लौटाने की क्षमता को प्रभावित करेगी:
 

स्पष्टीकरण – ऐसे मामलों में, चूककर्ता अधिकारी से अधिक सूचक राशि (आईए) की मांग की जा सकेगी।
  2. कथित चूक में आवेदक की भागीदारी बहुत ही कम रही हो;
  3. अग्रसक्रिय और असाधारण सहयोग, जिसमें शामिल हैं –
    - क. अपने आप ही किसी गलत कार्य (जो संदिग्ध हो या सामने न आया हो) की त्वरित और विस्तृत पहचान करना;
    - ख. अपने आप ही किए गए उल्लंघनों की शीघ्र पहचान करना और उसके बाद गहन आंतरिक समीक्षाएँ करवाना तथा सामने आए तथ्यों को साझा करना;
    - ग. अन्वेषण या जाँच में सबूत प्राप्त करके और उसे उपलब्ध करवाकर पर्याप्त रूप से सहयोग करना।
  4. किसी गलत कार्य का पता चलने और उसके संबंध में हस्तक्षेप किए जाने से पहले ही बोर्ड के समक्ष ईमानदारी से जिम्मेदारी स्वीकार करना तथा बोर्ड को उस गलत कार्य की जानकारी देना;
  5. स्वेच्छा से पर्याप्त सुधारात्मक कदम उठाना, ताकि गलत कार्य दोबारा न हो;
  6. जहाँ रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षा का पालन करने में 7 दिनों से कम की देरी हुई हो और रिपोर्टिंग न करने के कारण किसी व्यक्ति को अनुचित मुनाफा या नुकसान न हुआ हो;
  7. स्वेच्छा से मुआवज़ा प्रदान करना, कमीशन का प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट) करना, लाभ देना और निवेशकों को पैसा लौटाना;

8. गलत फॉर्मेट में प्रकटीकरण करना;
  9. आवेदक सरकारी प्राधिकरण की यूनिट हो, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट भी शामिल है।
- II. संबंधित कारकों पर विचार करते समय, आंतरिक समिति (आईसी) या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (एचपीएसी) या पूर्ण-कालिक सदस्यों का पैनल गंभीरता को बढ़ाने वाले वाले निम्नलिखित सामान्य कारकों (जनरल एग्रेवेटिंग फैक्टर्स) पर विचार कर सकेगा, जिसका आधार मान '0.2' होगा जो केवल एक बार ही लगाया जाएगा फिर चाहे सभी के लिए लगाया जाए या किसी एक या एक से अधिक के लिए लगाया जाए:
1. अन्वेषण, जाँच या सिविल एवं प्रशासनिक कार्यवाही, जिसमें निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ भी शामिल हैं, को लंबे समय तक खींचने या उसे विफल करने का प्रयास करना;
  2. गलत या भ्रामक गवाही आदि देना या सूचना प्रदान करना अथवा जानबूझकर वह सूचना प्रदान न करना जिसे प्रदान करना उसके लिए जरूरी था;
  3. लंबे समय तक (जिसकी अवधि 30 दिनों से कम की न हो) गलत कार्य करना;
  4. ग्राहकों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाना, जो कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो;
  5. आवेदक ने पूर्व विनियामक मार्गदर्शन और पूर्व चेतावनियों को अनसुना कर दिया हो;
  6. योजना बनाकर, पहले से सोच-समझकर या जटिल तरीके अपनाकर गलत कार्य करने का सबूत;
- स्पष्टीकरण: फर्जी एंट्रिटियों, कारपोरेट शेल्स या अपतटीय वित्तीय लेखों (ऑफशोर फाइनेंशियल अकाउण्ट्स) का इस्तेमाल करके विभिन्न देशों में चूक करने, आस्तियों (असेट्स) या लेनदेनों (ट्रांजेक्शन) को छिपाने, अथवा दोनों कार्य करना आम तौर पर जटिल तरीकों को दर्शाता है।
7. सूचीबद्ध मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या प्रतिभूति बाजार की बुनियादी संस्था को काफी जोखिम में डाला गया:
- स्पष्टीकरण. - सूचीबद्ध मध्यवर्ती या प्रतिभूति बाजार की बुनियादी संस्था को काफी जोखिम में माना जाएगा, यदि कथित चूक के परिणामस्वरूप:
- क. वह दिवालिया हो गई हो या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) के तहत आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो;
  - ख. वह, माँग किए जाने पर, जनता की किन्हीं जमाराशियों (डिपॉज़िट), भुगतान या निवेश की पूरी रकम लौटाने (का रिफंड) करने में असमर्थ रही हो;
  - ग. उसकी आस्तियाँ (असेट्स) इतनी कम हो गई हों कि किसी दूसरी संस्था में मजबूरन उसका विलय करना पड़ा हो, ताकि कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे।
8. सार्वजनिक रूप से व्यापारित कंपनी (पब्लिकली ट्रेडिड कंपनी) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) बहुत ही कम हो गई हो, अर्थात् उसे असूचीबद्ध (डिलिस्ट) कर दिया गया हो या उस कंपनी की प्रतिभूतियों के व्यापार (की ट्रेडिंग) को एक पूरे व्यापारिक दिवस (ट्रेडिंग डे) से अधिक की अवधि के लिए रोका गया हो ;

9. आवेदक ने भरोसे के पद का दुरुपयोग इस तरह से किया या विशेष कौशल का इस तरह से उपयोग किया कि उससे कथित चूक करना या उसे छिपाना काफी आसान हो गया ;

स्पष्टीकरण 1. – यह कारक तब लागू होगा, जब आवेदक के पास भरोसे का पद हो और उसने उसका दुरुपयोग किया हो। यह साधारण टिप्पणी पर लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2. – यह कारक तब लागू होगा, जब आवेदक के पद [जिसके तहत प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या उत्पादों को नियमित रूप से सृजित करना, निर्गमित (इश्यू करना), खरीदना, बेचना या उनका व्यापार (उनकी ट्रेडिंग) करना अथवा ऐसा करने में पेशेवर तरीके से सहायता देना शामिल है] का इस्तेमाल इस तरह से किया गया कि उससे चूक करना या उसे छिपाना काफी आसान हो गया। यह संगठन के लिपिक श्रेणी के स्टाफ पर लागू नहीं होगा; क्योंकि इस पद में आम तौर पर विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती।

स्पष्टीकरण 3.- 'विशेष कौशल' का अर्थ है - ऐसा कौशल जो आम लोगों के पास नहीं होता और जिसके लिए पेशेवर शिक्षा, प्रशिक्षण या लाइसेंसिंग [जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, लेखापरीक्षक (ऑडिटर), अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर), आदि] अपेक्षित होती है।

स्पष्टीकरण 4. – यह कारक वहाँ भी लागू होगा, जहाँ आवेदक ने यह जताया हो कि वह भरोसे के पद पर है, जबकि वास्तविकता ऐसी न हो।

10. आवेदक की-ऑपरेटर था, फिर चाहे उसने स्वयं व्यापार (ट्रेड) किया हो या न किया हो:

स्पष्टीकरण 1: कोई व्यक्ति की-ऑपरेटर होगा, यदि वह गैर-कानूनी गतिविधियों का संयोजक रहा हो या उसमें उसकी मुख्य भूमिका रही हो अथवा चूक का फायदा पाने वाला मुख्य व्यक्ति रहा हो:

परंतु यह कि, यदि व्यक्ति मात्र प्रबंधक या पर्यवेक्षक हो (किंतु वह संयोजक न रहा हो या उसकी मुख्य भूमिका न रही हो या वह फायदा पाने वाला मुख्य व्यक्ति न हो) तो वह की-ऑपरेटर नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2. – आंतरिक समिति (आईसी) या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (एचपीएसी) या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल इन कारकों पर भी विचार कर सकेगा, जैसे मुनाफे में कितनी हिस्सेदारी रही, अपराध में साथ देने वालों को शामिल कैसे किया गया, दूसरों पर कितना नियंत्रण और प्राधिकार रहा।

11. धोखाधड़ी करके जारी की गई या फर्जी प्रतिभूतियों अथवा उपयुक्त मंजूरी के बिना जारी (निर्गमित) की गई प्रतिभूतियों का उपयोग करके प्रबंध-मंडल पर नियंत्रण;

12. मिथ्या जानकारी की रिपोर्टिंग।

III. संबंधित कारकों पर विचार करते समय, आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकेगा जो यह दर्शाते हों कि कथित चूक जानबूझकर की गई थी, जिसका आधार मान '0.25' होगा जो केवल एक बार ही लगाया जाएगा फिर चाहे सभी के लिए लगाया जाए या किसी एक या एक से अधिक के लिए लगाया जाए:

1. लागू आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य नहीं किए गए;

2. व्यक्ति ने उल्लंघन संबंधी ऐसे निर्णय जानबूझकर लिए जो उसके प्राधिकार में नहीं थे;



3. व्यक्ति का इरादा उल्लंघन से मुनाफा पाने का था, फिर चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से;
4. कथित चूक बार-बार की गई।
- IV. संबंधित कारकों पर विचार करते समय, आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकेगा जो यह दर्शाते हों कि कथित चूक लापरवाही से की गई थी, जिसका आधार मान '0.3' होगा:
1. निगमित निकाय या जिम्मेदार व्यक्ति को पता हो कि उनके कुछ करने या न करने से प्रतिभूति विधियों का उल्लंघन होने का जोखिम हो सकता है और वह उस जोखिम को कम करने में पूरी तरह से असफल रहा हो:
- स्पष्टीकरण. - निम्नलिखित को लापरवाही समझा जाएगा,-
- क. कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारियों [जिनमें अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) भी शामिल हैं] की नियुक्ति करने में असफल रहना ;
- ख. समुचित प्रणालीगत रक्षोपाय करने में असफल रहना ; या
- ग. आचार संहिता निर्धारित करने में असफल रहना ।
- V. विभिन्न कारकों और कुल आधार मान पर विचार करते समय, निम्नलिखित विशिष्ट आधार मान को भी ध्यान में रखा जाएगा,—

सारणी-IV – सामान्य आधार मान, सभी मामलों में लागू		
चूक का स्वरूप		आधार मान
क.	कपटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहार; या अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) [जिसमें टिप्पिंग (अंतरंग व्यापार) भी शामिल है] अथवा आचार संहिता का उल्लंघन, जो कपटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहार या अंतरंग व्यापार से संबंधित अन्वेषण या जाँच के दौरान नोट किया गया	0.25
	या कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अंतरंग व्यापार करने के साथ-साथ आचार संहिता या किसी अन्य विनियम का उल्लंघन	0.3
	या कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार तथा अंतरंग व्यापार या कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार करने के साथ-साथ धन-शोधन निवारण तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी अपेक्षा का उल्लंघन	0.35
	या बाजार की बुनियादी संस्था (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशन) या उसके मुख्य अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष रूप से अपने कारबार का संचालन करने में असफलता	0.50

	<p>या बाजार की बुनियादी संस्था (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशन) या उसके मुख्य अधिकारियों के निष्पक्ष रूप से अपने कारबार का संचालन करने में असफल रहने के साथ-साथ उनके द्वारा कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अंतरंग व्यापार करना अथवा आचार संहिता या किसी अन्य विनियम का उल्लंघन करना</p>	<p>0.75</p> <p>[एक से अधिक मान के लागू होने के मामले में, वह मान लागू होगा जो सबसे अधिक हो।]</p>
ख.	<p>चूक के संबंध में व्यापारित मात्रा (वॉल्यूम ट्रेडेड) और / या कीमत- परिवर्तन के कारक</p>	<p>'बी', 'पी' और 'क्यू' का योग (जहाँ कहीं भी लागू हो) समूह के प्रत्येक सदस्य या आवेदक (जब वह अकेले कार्य करता हो) पर केवल उसी स्थिति में लागू होगा, यदि, यथास्थिति समूह (जिसका आवेदक हिस्सा है) के अथवा आवेदक (जब वह अकेले कार्य करता हो) के संबंध में व्यापारित मात्रा या कीमत- परिवर्तन, व्यापारित संख्या की गणना, यथास्थिति, अन्वेषण रिपोर्ट या जाँच या कारण बताओ सूचना या आदेश में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर की जा सकती हो।</p> <p>यदि व्यापार (ट्रेडिंग) की एक से अधिक अवधियाँ हों, तो उस अवधि पर विचार किया जाएगा जिसके दौरान सबसे अधिक परिवर्तन दर्ज किया गया हो।</p>
ग.	<p>अनुचित (गलत) तरीके से कमाए गए मुनाफों का <u>आवधिक मान</u>*</p>	<p>0.09 x चूक किए जाने की तारीख से कलेंडर वर्षों की संख्या</p>
घ.	<p>निपटान के उन सभी मामलों में प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम, जिनमें</p>	<p>सभी आवेदक : 0.25</p>

	प्रतिभूति विधियों (सिक्कुरिटीज़ लॉज़) का उल्लंघन स्वीकार न किया गया हो	
ड.	अर्थसुलभता रहित (इल-लिक्विड) स्क्रिप के मामले में किया गया उल्लंघन	0.3
च.	जो व्यक्ति गरीब हों अथवा जिनकी समापन (लिक्विडेशन) या दिवाला प्रक्रिया चल रही हो या जिनकी समाधान / चुकौती (रीपेमेंट) योजना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (अड्जुडिकेटिंग ऑफिसर) के पास मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जा चुकी हो	-0.3

\*कारक 'ग' केवल उन्हीं मामलों में लागू है, जहाँ वास्तविक मुनाफा और/या टाले गए नुकसान (लगभग) का निर्धारण किया जा सकता हो और ब्याज के साथ प्रत्यर्पण (डिस्सॉर्जमेंट) का आदेश न दिया गया हो। अवधि की गणना करते समय, अंशों (फ्रैक्शन) पर ध्यान न दिया जाए।

'वी' = उल्लंघन की पूरी अवधि के दौरान व्यापार (ट्रेडिंग) की किसी अवधि में व्यापारित मात्रा के उच्चतम % के लिए मान

एक से अधिक स्क्रिप के मामले में, उच्चतम व्यापारित मात्रा वाली स्क्रिप पर विचार किया जाए

सारणी-IVक – विशेष आधार मान, सामान्य आधार मान के अलावा		
व्यापारित मात्रा का % [अर्थसुलभता-रहित (इल-लिक्विड) स्क्रिप]	'वी'	व्यापारित मात्रा का % [अर्थसुलभ (लिक्विड) स्क्रिप]
50% तक	0.1	2% तक
50-60%	0.15	2-5%
60-75%	0.2	5-10%
75% या उससे अधिक	0.25	10% या उससे अधिक

"पी" = उल्लंघन की पूरी अवधि के दौरान कीमत-परिवर्तन के उच्चतम % के लिए मान

एक से अधिक स्क्रिप के मामले में, सर्वाधिक कीमत-परिवर्तन वाली स्क्रिप पर विचार किया जाए

सारणी-IVख – विशेष आधार मान, सामान्य आधार मान के अलावा		
कीमत-परिवर्तन का % [अर्थसुलभता-रहित (इल-लिक्विड) स्क्रिप]	'पी'	कीमत-परिवर्तन का % [अर्थसुलभ (लिक्विड) स्क्रिप]
50% तक	0.1	5% तक
50-100%	0.15	5-10%
100-200%	0.2	10-20%

200% या उससे अधिक	0.25	20% या उससे अधिक
-------------------	------	------------------

**'क्यू' = कीमत-परिवर्तन के उच्चतम % के लिए मान, चूक की अवधि के दौरान एफ एंड ओ एवं लीवरेज उत्पादों के लिए**

**एक से अधिक उत्पादों (प्रोडक्ट) के मामले में, उस संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर विचार किया जाए जिसमें सबसे अधिक कीमत-परिवर्तन दर्ज किया गया हो**

<b>सारणी-IVग – विशेष आधार मान, सामान्य आधार मान के अलावा</b>	
<b>कीमत-परिवर्तन का %</b>	<b>"क्यू"</b>
<b>0.5% तक</b>	<b>0.1</b>
<b>0.5-1%</b>	<b>0.15</b>
<b>1-5%</b>	<b>0.2</b>
<b>5% या उससे अधिक</b>	<b>0.25</b>

**सारणी-V – विशेष आधार मान, सामान्य आधार मान के अलावा - प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) एवं खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) से संबंधित चूकों के लिए**

<b>उल्लंघन का स्वरूप</b>		<b>आधार मान</b>
<b>क.</b>	अधिग्रहण (टेकओवर), अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) अथवा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गमन (इश्युएंस) या उनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) से संबंधित विनियमों के तहत प्रकटीकरण न किए जाने (जिसमें गलत या अधूरा प्रकटीकरण भी शामिल है) के आरोप के साथ कोई अन्य आरोप	0.20
<b>ख.</b>	प्रकटीकरण न किए जाने (जिसमें गलत या अधूरा प्रकटीकरण भी शामिल है) के मामलों में : आवेदक ने किसी अन्य विनियम के तहत संबंधित प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किया है या वह निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) है जिसकी समादत्त (पेड-अप) इक्विटी शेयर पूँजी [आरक्षितियों (रिज़र्व) सहित] दस करोड़ रुपये से कम हो [उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो केवल धारिता (नियंत्रि / होल्डिंग) कंपनी हों]	-0.5
<b>ग.</b>	खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) संबंधी उल्लंघनों में : अधिग्रहण लागू होने से पहले लक्षित कंपनी अर्जनकर्ता के नियंत्रण में न हो	0.25

VI. कई आवेदकों के मामले में जहाँ संयुक्त और पृथक देनदारी (दायित्व) होती हो, वहाँ कई आवेदकों के लिए निकाली गई सूचक राशि (इंडीकेटिव अमाउंट) के संबंध में, एक सूचक राशि आम तौर पर चूक के संबंध में लागू कारकों तथा भारों के आधार पर निकाली जा सकेगी, जैसा आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल उचित समझे, और किसी एक आवेदक से अपेक्षित राशि के संबंध में कोई सीमा लगाते समय किसी अन्य कारक पर भी विचार किया जा सकेगा।

### **अध्याय-VI**

### **लागू आधार राशि**

**लागू आधार राशि = 'गैरकानूनी तरीके से कमाए गए मुनाफे' + 'निवेशकों को हुआ नुकसान' [जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार निकाला गया हो]**

**या**

**इस अध्याय की सारणियों के अनुसार आधार राशि,  
जो भी ज्यादा हो**

सामान्य दिशानिर्देश: यदि आवेदक पर खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) से संबंधित विनियमों [भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त वर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त वर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, तथा बाद में जारी इसी तरह के किसी विनियम] और अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) के प्रतिषेध से संबंधित विनियमों [भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, और बाद में जारी इसी तरह के किसी विनियम] के तहत प्रकटीकरण न किए जाने का आरोप हो, तो ऐसे आरोप (आरोपों) के लिए निकाली गई आधार राशि में से सबसे अधिक राशि 75% तक घटा दी जाएगी।

<b>सारणी-VI</b>		
<b>खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) से संबंधित कथित चूक के लिए आधार राशि</b>		
<b>उल्लंघन का स्वरूप</b>	<b>वर्जनकर्ता (एक्ज़ायरर) और सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए आधार राशि</b>	
<b>देरी से लाया गया खुला प्रस्ताव</b>	25 लाख रुपये या खुले प्रस्ताव के आकार का 0.25%, अर्थात् उन शेयरों की अधिकतम संख्या जिनके लिए खुला प्रस्ताव लाया जाना चाहिए x खुले प्रस्ताव की लागू कीमत, जो भी ज्यादा हो	
<b>देरी से लाया गया खुला प्रस्ताव (बोर्ड से निदेश मिलने के बाद)</b>	50 लाख रुपये या खुले प्रस्ताव के आकार का 0.5%, जो भी ज्यादा हो	
<b>जहाँ खुला प्रस्ताव लाना बेकार हो जाए, अर्थात् जब कंपनी असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो गई हो, जब खुला प्रस्ताव शेयरधारकों के लिए फायदाप्रद न हो, आदि</b>	<b>उस कंपनी के किसी क्रियाकलाप की वजह से बेकार हो जाना, जिससे खुला प्रस्ताव लाने की अपेक्षा हो</b>	<b>किसी अन्य कारण की वजह से बेकार हो जाना, जैसे खुला प्रस्ताव शेयरधारकों के लिए फायदाप्रद न हो</b>
	1 करोड़ रुपये या खुले प्रस्ताव का आकार, जो भी ज्यादा हो	न्यूनतम शास्ति और खुले प्रस्ताव में होने वाले संभावित खर्च के बीच की कोई रकम, जैसी बोर्ड के निगम वित्त विभाग (कारपोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट / सीएफडी) की सिफारिश हो

सारणी-VII			
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम-1997/2011 के तहत प्रकटीकरणों (डिस्क्लोजर) से संबंधित कथित चूक के लिए आधार राशि			
शेयरधारिता या मताधिकारों का प्रतिशत, जिनका अर्जन किया गया हो या जिन्हें बेचा आदि गया हो किंतु जिनका प्रकटीकरण न किया गया हो अथवा ऋण-भार वाले शेयरों का प्रतिशत जिनका प्रकटीकरण न किया गया हो, आदि	आधार राशि		
	वर्ष 1997 के विनियमों के विनियम 7 या वर्ष 2011 के विनियमों के विनियम 29 के उल्लंघन के लिए (I)	वर्ष 1997 के विनियमों के विनियम 8 या वर्ष 2011 के विनियमों के विनियम 30 के उल्लंघन के लिए (II)	वर्ष 1997 के विनियमों के विनियम 8क या वर्ष 2011 के विनियमों के विनियम 31 के उल्लंघन के लिए (III)
2% से कम	2 लाख रुपये + 5,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए		
कम से कम 2% (किंतु 5% से कम)	5 लाख रुपये + 10,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए		
कम से कम 5% (किंतु 10% से कम)	10 लाख रुपये + 15,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए		
कम से कम 10% (किंतु 15% से कम)	15 लाख रुपये + प्रकट न की गई धारिता (होल्डिंग), आदि के मूल्य का 0.1 % + 20,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए		
15% और उससे अधिक	20 लाख रुपये + प्रकट न की गई धारिता (होल्डिंग), आदि के मूल्य का 0.1 % + 25,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए		

**सारणी-VII की टिप्पणियाँ:**

- सारणी-VII उन मामलों में लागू नहीं है, जहाँ प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) संबंधी उल्लंघन कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफ्यूटीपी) या अंतरंग व्यापार (आईटी) के साथ-साथ किया गया हो।  
स्पष्टीकरण: उस समय किए गए लेनदेन (डीलिंग) को अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) माना जा सकेगा, जब महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी या शेयरधारिता संबंधी जानकारी हो।
- ऊपर (II) में उल्लिखित उल्लंघन के लिए आधार राशि केवल निम्नतम स्तर के अनुसार ही होगी, फिर चाहे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान शेयरधारिता में कितना भी बदलाव हुआ हो।

जो प्रकटीकरण वार्षिक आधार पर किए जाते हों, उन प्रकटीकरणों से संबंधित उल्लंघनों के मामले में, प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए रकम की गणना प्रकटीकरण से संबंधित पहले उल्लंघन के लिए ही की जाएगी। यदि नोटिसी कुछ वर्षों तक वार्षिक रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन करता है, तो इस प्रकार कुछ वर्षों तक किए गए पालन के मद्देनजर रकम इस तरह से तय की जाएगी कि वह लगातार उल्लंघन किए जाने के मामलों में तय की जाने वाली रकम से ज्यादा न हो।

3. देरी की अवधि की गणना उस अंतिम दिन से की जाएगी, जिस दिन विनियमों के अनुसार प्रकटीकरण (डिक्लोज़र) किया जाना चाहिए था।

सारणी-VIII	
आधार राशि - अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध विनियम, 1992 के विनियम 13(3), 13(4), 13(4क) और तत्स्थानी विनियम 13(6) के तहत लेनदेन (ट्रांजैक्शन) से संबंधित प्रकटीकरणों [जिनमें अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध विनियम, 2015 के विनियमों के तहत लेनदेन (ट्रांजैक्शन) से संबंधित वैसे ही प्रकटीकरण शामिल हैं] के संबंध में कथित चूक	
शेयरधारिता या मताधिकारों का प्रतिशत, जिनका अर्जन किया गया हो या जिन्हें बेचा आदि गया हो किंतु जिनका प्रकटीकरण न किया गया हो अथवा ऋण-भार वाले शेयरों का प्रतिशत जिनका प्रकटीकरण न किया गया हो, आदि	आधार राशि
2% से कम	2.5 लाख रुपये + 7,500 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए
कम से कम 2% (किंतु 5% से कम)	6 लाख रुपये + 12,500 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए
कम से कम 5% (किंतु 10% से कम)	12 लाख रुपये + 17,500 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए
कम से कम 10% (किंतु 15% से कम)	18 लाख रुपये + प्रकट न की गई धारिता (होल्डिंग), आदि के मूल्य का 0.1% + 22,500 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए
15% और उससे अधिक	25 लाख रुपये + प्रकट न की गई धारिता (होल्डिंग), आदि के मूल्य का 0.1% + 25,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए

सारणी-VIII की टिप्पणियाँ :

- संबंधित व्यक्तियों या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों की ओर से हुए प्रकटीकरण संबंधी उल्लंघनों के संबंध में, आधार राशि 25% तक बढ़ाई जा सकती।
- सारणी-VIII उन मामलों में लागू नहीं है, जहाँ प्रकटीकरण (डिक्लोज़र) संबंधी उल्लंघन कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफ्यूटीपी) या अंतरंग व्यापार (आईटी) के साथ-साथ किया गया हो।

**स्पष्टीकरण:** उस समय किए गए लेनदेन (डीलिंग) को अंतरंग व्यापार माना जा सकेगा, जब महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी या शेयरधारिता संबंधी जानकारी हो।

सारणी-IX	
आधार राशि - प्रकटीकरणों से संबंधित उल्लंघन - जिनका उल्लेख सारणी-VII और सारणी-VIII में नहीं किया गया है	
कथित चूक का स्वरूप	आधार राशि
प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) से संबंधित उल्लंघन का प्रकार	
अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध (पीआईटी) संबंधी विनियम	
समय-समय पर किए जाने वाले तथा अन्य प्रकटीकरण	5 लाख रुपये + 5,000/- रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए (यदि लागू हो)
खुले प्रस्ताव संबंधी विनियम	
रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ या प्रकटीकरण जिनके लिए छूटें उपलब्ध हैं, उन मामलों को छोड़कर जहाँ छूट का लाभ उठाने के लिए पहले पूरी की जाने वाली शर्त का पालन न किए जाने के परिणामस्वरूप खुला प्रस्ताव लाने की बाधयता लागू हो जाए (वर्ष 1997 के विनियमों का विनियम 6 पुराना हो गया है और इसके उल्लंघन के लिए कोई राशि नहीं ली जा सकती, उस मामले को छोड़कर जहाँ केवल विनियम 6 का ही उल्लंघन किया गया हो, वहाँ न्यूनतम निपटारे की रकम लागू हो सकेगी)	5 लाख रुपये + 10,000/- रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए (यदि लागू हो)
विदेशी संस्थागत निवेशकों से संबंधित विनियमों के तहत उल्लंघन	
जानकारी प्रदान करने में असफल रहना	20 लाख रुपये प्रति चूक
महत्वपूर्ण बदलाव सूचित करना	10 लाख रुपये प्रति चूक
शेष	
आचार संहिता संबंधी रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ या निदेशक की नियुक्ति संबंधी प्रकटीकरण या प्रकटीकरण संबंधी कोई अन्य उल्लंघन जिनका उल्लेख इस अध्याय में नहीं किया गया है, यदि उचित समझा जाए	5 लाख रुपये + 10,000/- रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए (यदि लागू हो)

**सारणी-IX की टिप्पणियाँ:**

1. प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों की ओर से हुए प्रकटीकरण संबंधी उल्लंघनों के संबंध में आधार राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी।
2. सारणी- IX उन मामलों में लागू नहीं है, जहाँ प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी उल्लंघन कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफ्यूटीपी) या अंतरंग व्यापार (पीआईटी) के साथ-साथ किया गया हो।

**स्पष्टीकरण:** यदि लेनदेन महत्वपूर्ण वित्तीय या शेयरधारिता संबंधी जानकारी रखते हुए किया गया हो, तो उसे अंतरंग व्यापार माना जा सकेगा।

सारणी-X							
प्रत्येक आवेदक की हर कथित चूक के लिए या संयुक्त देनदारी (दायित्व) के आधार पर शेष आधार राशि (संयुक्त आवेदकों के मामले में लागू राशि के बोध के अनुसार)							
व्यक्ति (मुख्य अधिकारी शामिल नहीं है) (I)	निमित्त निकाय (बॉडी कारपोरेट) एवं फर्म [और निमित्त निकाय /	मुख्य अधिकारी और अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) [जब II, IV-VII में न हों] (III)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ब (15बी) एवं 15च (एफ)	निवेशक शिकायतों का निवारण करने में असफल रहना [और मध्यवर्ती / निर्गमकर्ता के साथ संयुक्त देनदारी (दायित्व) से संबंधित मामलों में	बाजार की बुनियादी संस्थाएँ [और संस्था के साथ संयुक्त देनदारी (दायित्व) से संबंधित मामलों में मुख्य अधिकारी] (VI)	पैसे (निधि / फंड) से संबंधित चूकें [और निधि के साथ संयुक्त देनदारी (दायित्व) से संबंधित मामलों में मुख्य अधिकारी] (VII)	



		फर्म के साथ संयुक्त देनदारी (दायित्व) से संबंधित मामलों में मुख्य अधिकारी] (II)		और ऐसी ही चूँके [और मध्यवर्ती के साथ संयुक्त देनदारी (दायित्व) से संबंधित मामलों में मुख्य अधिकारी] (IV)	मुख्य अधिकारी] (V) (देरी के लिए 1/4 घट जाएगा)		
<p><b>आधार राशि जहाँ :</b></p> <p>प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफ्यूटीपी) वा अंतरंग व्यापार (आईटी) से संबंधित चूक,</p> <p>प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट) में मिथ्या / भ्रामक / गलत / अशुद्ध प्रकटीकरण,</p> <p>बाजार की बुनियादी संस्थाओं द्वारा उस प्रकार कारबार का संचालन न किया जा रहा हो जैसा अपेक्षित हो,</p> <p>लापरवाही बरतकर किया गया उल्लंघन,</p> <p>या</p> <p>प्रत्यर्पण (डिस्मिजमेंट) / धन-वापसी (रिफंड) की रकम 1 करोड़ रुपये से अधिक हो (ड)</p>	15 लाख रुपये	1 करोड़ रुपये	45 लाख रुपये	15 लाख रुपये	30 लाख रुपये	5 करोड़ रुपये	<p>33 लाख रुपये</p> <p>या</p> <p>उल्लंघन के समय, औसत प्रबंधनाधीन आस्तियों (असेट अंडर मैनेजमेंट) का 0.1%</p> <p>या</p> <p>उल्लंघन के समय, औसत शुद्ध मालियत (नेटवर्थ) का 0.5%</p> <p>(जो भी अधिक हो)</p>
<p><b>बेचमार्क जहाँ उल्लंघन वह हो जिसका उल्लेख (ड) में किया गया है और,-</b></p>	60 लाख रुपये	3 करोड़ रुपये	2 करोड़ रुपये	60 लाख रुपये	80 लाख रुपये	10 करोड़ रुपये	<p>60 लाख रुपये</p> <p>या</p> <p>उल्लंघन के समय, औसत प्रबंधनाधीन आस्तियों का</p>

ऐसे उल्लंघन से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से –  (I) अन्य व्यक्तियों को काफी नुकसान हुआ हो,  (II) अन्य व्यक्तियों को काफी नुकसान होने का काफी जोखिम पैदा हो गया हो, या,  (III) प्रतिभूति बाजारों की सत्यनिष्ठा पर असर पड़ा हो (ड)							0.05% या उल्लंघन के समय औसत शुद्ध मालियत (नेटवर्थ) का 0.075% (जो भी अधिक हो)
शेष (ण)	3 लाख रुपये	15 लाख रुपये	10 लाख रुपये	3 लाख रुपये	6 लाख रुपये	3 करोड़ रुपये	15 लाख रुपये  या  उल्लंघन के समय, औसत प्रबंधनाधीन आस्तियों का 0.001%  या उल्लंघन के समय, औसत शुद्ध मालियत (नेटवर्थ) का 0.01% (जो भी अधिक हो)

#### सारणी-X की टिप्पणियाँ :

1. एक से अधिक आधार राशि के लागू होने के मामले में, उस आधार राशि पर विचार किया जाएगा जो सबसे अधिक हो।
2. इस अनुसूची में, 'मुख्य अधिकारी' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 27 के तहत शामिल किया जा सकता हो।
3. 'पैसे' (निधि / फंड) का अर्थ है - आनुकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ), पारस्परिक निधि (एमएफ), सामूहिक निवेश स्कीम (सीआईएस) और पूलिंग का कोई दूसरा इंतजाम जिसके लिए बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण लेना जरूरी हो।
4. इस सारणी के (II) में उल्लिखित 'निगमित निकाय' में ऐसा कोई आवेदक शामिल है, जिसे (I) और (III) से (VII) में शामिल न किया गया हो।

**अध्याय-VII****बार-बार होने वाली चूक**

- I. चूक कितनी बार हुई है, इसका निर्धारण इस अध्याय में दी गई एक या एक से अधिक पद्धतियों का इस्तेमाल करके या एक से अधिक पद्धतियों को मिलाकर किया जा सकेगा।

*स्पष्टीकरण.* - एक ही वाद हेतुक (काँज़ ऑफ़ एक्शन) के संबंध में अलग-अलग व्यक्तियों की बाबत अलग-अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा एक उपयुक्त सूचक राशि (आईए) तय करने के लिए जरूरी हो।

- II. आम तौर पर, हर कथित चूक की गिनती निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक के आधार पर की सकेगी,-

- i. खरीद या बिक्री संबंधी लेनदेनों (ट्रांज़ैक्शन्स) की संख्या (लगभग),
- ii. व्यक्तिगत रूप से कितनी बार धोखा आदि देने की कोशिश की गई (लगभग),
- iii. कितने निवेशकों पर असर पड़ा (लगभग), या
- iv. 'कोर्स ऑफ़ कंडक्ट' स्टैण्डर्ड

- जिसके तहत हर बार की गई चूक एक पूरा-पूरा उल्लंघन है। प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए, विवेकाधिकार के आधार पर कोई ऐसा दूसरा मानक लागू किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा कड़ा न हो:

परंतु यह कि, जहाँ यह देखने में आए कि चूक काफी बार की गई है, वहाँ एक उपयुक्त सूचक राशि (आईए) तय करने के लिए किसी एक चूक का निर्धारण करने के लिए ऐसा मानक अपनाया जा सकता है, जो ज्यादा कड़ा न हो।

*स्पष्टीकरण.* - रिपोर्ट या कथन से संबंधित चूक के संबंध में,-

- i. प्रत्येक व्यक्ति को भेजी गई भ्रामक रिपोर्ट या किए गए भ्रामक कथन को अलग "कार्य" माना जा सकेगा;
- ii. प्रत्येक भिन्न भ्रामक रिपोर्ट या किया गया भिन्न भ्रामक कथन अलग "कार्य" हो सकेगा;
- iii. रिपोर्ट में किया गया प्रत्येक भिन्न भ्रामक कथन अलग "कार्य" हो सकेगा;
- iv. ऐसी सभी या किन्हीं रिपोर्टों या कथनों के संबंध में कोर्स ऑफ़ कंडक्ट स्टैण्डर्ड; या
- v. उपरोक्त i, ii, iii और iv में से कोई दो या दो से अधिक।

- III. **कोर्स ऑफ़ कंडक्ट स्टैण्डर्ड** : किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, एक उपयुक्त सूचक राशि (आईए) तय करने के उद्देश्य से, "कोर्स ऑफ़ कंडक्ट" स्टैण्डर्ड लागू किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत एक उल्लंघन के संबंध में कई बार की गई चूकों की गिनती एक ही उल्लंघन के रूप में की जाती है।

*स्पष्टीकरण 1.* - यदि एक ही चूक कई बार की गई हो, तो उसे एक ही चूक मानना तर्कसंगत हो सकेगा, यदि -

- (क) कार्य हेराफेरी करने, कपट करने या धोखा देने के इरादे से न किया गया हो या अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) न किया गया हो, सिवाय वहाँ जहाँ सूचक राशि (जिसकी सिफारिश की गई हो) कार्य की तुलना में कहीं ज्यादा हो;

**स्पष्टीकरण.** - "कहीं ज्यादा होने" और "उपयुक्त होने" का संदर्भ जिस बारे में भय पैदा करना हो उसकी तुलना में सूचक राशि के उपयुक्त होने और आवेदक द्वारा गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए मुनाफे या निवेशकों को पहुंचाए गए नुकसान की तुलना में सूचक राशि के उपयुक्त न होने से है।

(ख) कार्य से सार्वजनिक निवेशकों के अधिकारों को बहुत अधिक क्षति नहीं हुई हो, या यदि ऐसे मामलों में पैसा आदि वापस लौटा दिया गया हो; और

(ग) उल्लंघन प्रणाली संबंधी समस्या की वजह से हुए हों या ऐसे किसी कारण से हुए हों जिनके संबंध में निवारण कर लिया गया हो।

**स्पष्टीकरण 2.** - तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, उल्लंघनों की गिनती इस आधार पर की जा सकेगी कि उल्लंघन करना कितने दिन तक जारी रहा, हालाँकि यह जरूरी नहीं है कि समयावधि (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक) में एकरूपता हो। कई बार किए गए उल्लंघनों मिलाकर एक या एक से अधिक कोर्स ऑफ़ कंडक्ट माना जा सकेगा।

### अनुसूची-III

#### भाग-क

#### (विनियम 16 देखें)

फॉर्मेट

तारीख:

.....

पता

**विषय:** ..... के मामले में संक्षिप्त निपटारे की सूचना (नोटिस)

..... के मामले में अन्वेषण (इन्वेस्टीगेशन) / निरीक्षण / जाँच / लेखापरीक्षा (ऑडिट) के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने पहली नज़र में ही यह पाया है कि आपने प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन किया है:

- (i) .....
- (ii) .....
- (iii) .....
- (iv) .....

जो निष्कर्ष सामने आए हैं, उनके उद्धरण संलग्न हैं।

2. उपरोक्त के मद्देनज़र, आपके खिलाफ ..... (संबंधित प्रावधान, जिनके तहत कार्यवाहियाँ शुरू की जा सकती हैं या जारी रखी जा सकती हैं) के तहत संभावित कार्यवाहियाँ शुरू की जा सकती हैं या जारी रखी जा सकती हैं।
3. इस सूचना (नोटिस) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पास आपके खिलाफ शुरू की जाने वाली कार्यवाहियों और लगाए जाने वाले आरोपों में परिवर्तन करने का अधिकार आरक्षित है, और यह सूचना (नोटिस) निपटारे की मांग करने का या बोर्ड द्वारा शुरू की गई किसी कार्रवाई से बचने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के विनियम 5 के अध्याधीन, शुरू की जाने वाली उपरोक्त कार्यवाहियों का निपटारा तभी किया जा सकेगा, जब इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने की तारीख से 30 कलेंडर दिनों के भीतर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के अध्याय-II के तहत निपटारे का आवेदन दाखिल कर दिया जाए और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के ..... (प्रावधान) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को रु. .... की निपटारे की रकम प्रेषित कर दी जाए और निम्नलिखित गैर-आर्थिक शर्तों आदि का पालन कर लिया जाए (यदि लागू हों):

(i) .....

(ii) ..... [यदि कोई दूसरी शर्तें आदि हों, तो कृपया उनका उल्लेख करें]

5. यदि निपटारे का आवेदन दाखिल नहीं किया जाता है या निपटारे की रकम प्रेषित नहीं की जाती है और/या अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि के संबंध में वचन प्रस्तुत नहीं किया जाता है या बोर्ड के अनुसार संतोषजनक रूप से अन्य गैर-आर्थिक शर्तों आदि का पालन नहीं किया जाता है या निपटारे का आवेदन वापस ले लिया जाता है, तो निर्धारित कार्यवाहियाँ, यथास्थिति, शुरू की जा सकेंगी या जारी रखी जा सकेंगी, और आपको अगले चरण में केवल उन्हीं कार्यवाहियों की बाबत निपटारे का आवेदन दाखिल करने की अनुमति होगी, जो, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी (अड्जुडिकेटिंग ऑफिसर) या बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियाँ पूरी हो जाने के पश्चात् न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) के समक्ष लंबित हों।

नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

**भाग-ख**  
**(विनियम 18 देखें)**  
**फॉर्मेट**

तारीख

.....

पता

**विषय: ..... के मामले में निपटारे की सूचना (नोटिस)**

..... के मामले में अन्वेषण (इन्वेस्टीगेशन) / निरीक्षण / जाँच / लेखापरीक्षा (ऑडिट) के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने पहली नज़र में ही यह पाया है कि आपने प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन किया है:

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

(iv) .....

जो निष्कर्ष सामने आए हैं, उनके उद्धरण संलग्न हैं।

2. उपरोक्त के मद्देनज़र, आपके खिलाफ ..... **(संबंधित प्रावधान, जिनके तहत कार्यवाहियाँ शुरू की जा सकती हैं या जारी रखी जा सकती हैं)** के तहत संभावित कार्यवाहियाँ शुरू की जा सकती हैं या जारी रखी जा सकती हैं।
3. इस सूचना (नोटिस) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पास आपके खिलाफ शुरू की जाने वाली कार्यवाहियों और लगाए जाने वाले आरोपों में परिवर्तन करने का अधिकार आरक्षित है, और यह सूचना (नोटिस) निपटारे की मांग करने का या बोर्ड द्वारा शुरू की गई किसी कार्यवाई से बचने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के विनियम 5 के अध्यक्षीन शुरू की जाने वाली उपरोक्त कार्यवाहियों का निपटारा, तभी किया जा सकेगा, जब इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने की तारीख से 15 कलेंडर दिनों के भीतर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के अध्याय-II के तहत निपटारे का आवेदन दाखिल कर दिया जाए।
5. यदि निपटारे का आवेदन दाखिल नहीं किया जाता है, तो बोर्ड आपके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाहियाँ शुरू कर सकता है और आपको अगले चरण में केवल उन्हीं कार्यवाहियों की बाबत निपटारे का आवेदन दाखिल करने की अनुमति होगी, जो, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी (अड्जुडिकेटिंग ऑफिसर) या बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियाँ पूरी हो जाने के पश्चात् न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) के समक्ष लंबित हों।

नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

#### अनुसूची-IV

(विनियम 19 देखें)

#### गोपनीयता के लिए आवेदन

1. गोपनीयता के लिए आवेदन का फॉर्मेट ऐसा होगा जो आवेदक के लिए सुविधाजनक हो और जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे,-
  - i. आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और साथ ही कथित चूक में शामिल अन्य व्यक्तियों (जिनका पता हो) का नाम और पता;
  - ii. पत्र-व्यवहार आदि के लिए का आवेदक का पता (जिसमें दूरभाष संख्याएँ और ई-मेल आदि भी शामिल हों);
  - iii. कथित चूक (अरेंजमेंट) का विस्तृत विवरण, जिसमें उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख हो, तथा ऐसे लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्यों आदि का विवरण;
  - iv. चूक कब से हुई और चूक की अवधि
  - v. उन सभी व्यक्तियों के नाम, पद, कार्यालय का पता और जहाँ कहीं भी जरूरत हो, उनके घर के पते, जो आवेदक की जानकारी में कथित चूककर्ता हों या कथित चूककर्ताओं (उन व्यक्तियों सहित जो आवेदक की ओर से शामिल हों) से उनका संबंध रहा हो।

- vi. अन्य प्राधिकरणों, मंचों (फोरम), या न्यायालयों के विवरण (यदि कोई हों), जिनसे कथित उल्लंघन के संबंध में संपर्क किया गया या संपर्क करने का इरादा है;
- vii. गोपनीयता के लिए किए गए आवेदन के समर्थन में दिए गए सबूत की विस्तृत सूची (जिसमें यह उल्लेख हो कि दिया गया सबूत किस तरह का है और उसकी विषय-वस्तु क्या है); और
- viii. कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा बोर्ड द्वारा निदेश दिया जाए।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

[निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) आवेदक का स्टाम्प और मुहर]

### सत्यापन

मैं, ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी (नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें)

श्री ....., आवेदक / ..... का प्राधिकृत प्रतिनिधि [निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में] होने के नाते, एतद्वारा यह सत्यापित करता / करती हूँ और शपथ पर यह स्वीकार करता / करती हूँ कि यह आवेदन और इसमें दी गई बातें मेरी जानकारी एवं विश्वास तथा रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं और यह कि मैंने कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाए हैं और मैं ऐसी किसी अन्य संबंधित जानकारी से बोर्ड को बिना किसी देरी के अवगत कराता रहूंगा जो भी मुझे पता चले।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान :

2. गोपनीयता के लिए किए गए आवेदन के साथ अनुसूची-1 के भाग-ग में यथा निर्धारित वचन और अधित्यजन (वेवर) संलग्न होंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा. /378/18]

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 30th November, 2018

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SETTLEMENT PROCEEDINGS) REGULATIONS, 2018

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/48.**—*In exercise of the powers conferred by Section 15JB of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 23JA of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 19-IA of the Depositories Act, 1996 read with Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to provide for the terms of settlement and the procedure of settlement and matters connected therewith or incidental thereto, namely:—*

## CHAPTER I PRELIMINARY

### Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018.  
(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of January 2019.

### Definitions

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below and their cognate expressions shall be construed accordingly, –
- (a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
  - (b) "alleged default" means an alleged or probable contravention of any provision of the securities laws;
  - (c) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under the provisions of Section 3 of the Act;
  - (d) "Panel of Whole Time Members" means the panel consisting of two or more Whole Time Members of the Board;
  - (e) "securities laws" means the Act, the Securities Contract (Regulations) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the relevant provisions of any other law to the extent it is administered by the Board and the relevant rules and regulations made thereunder;
  - (f) "specified proceedings" means the proceedings that may be initiated by the Board or have been initiated and are pending before the Board or any other forum, for the violation of securities laws, under Section 11, Section 11B, Section 11D, sub-Section (3) of Section 12 or Section 15-I of the Act or Section 12A or Section 23-I of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or Section 19 or Section 19H of the Depositories Act, 1996, as the case may be;
  - (g) "Tribunal" means the Securities Appellate Tribunal established under Section 15K of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.
- (2) Words and expressions used but not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 the Depositories Act, 1996 the Companies Act, 2013 or any of the rules or regulations made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto.

## CHAPTER II APPLICATION FOR SETTLEMENT

### Application

3. (1) A person against whom any specified proceedings have been initiated and are pending or may be initiated, may make an application to the Board in the Form specified in Part-A of the Schedule-I.
- (2) The application made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Part-B of Schedule I and the undertakings and waivers as specified in Part-C of Schedule-I:
- Provided that the rejection or withdrawal of the application shall not affect the continued validity of the undertakings and waivers given in respect of limitation or laches in respect of the initiation or continuation or restoration of any legal proceeding and the waivers given under sub-paras (d), (e), (f) and (g) of para 12 of the undertaking and waivers as provided in Part-C of the Schedule-I and subject to such undertakings and waivers, the Board or the applicant, shall be free to initiate or pursue such proceedings as may be appropriate in accordance with law.
- (3) The applicant shall make full and true disclosures in the application in respect of the alleged default(s):
- Provided that the facts established against the applicant or admitted in any ongoing or concluded proceedings in India or outside India, with respect to the same cause of action, under any law, shall be deemed to be admitted by the applicant in respect of the proceedings proposed to be settled.
- (4) The applicant shall make one application for settlement of all the proceedings that have been initiated or may be initiated in respect of the same cause of action.
- (5) An application that is not complete in all respects or does not conform to the requirements of these regulations shall be returned to the applicant.
- (6) The applicant whose application has been returned under sub-regulation (5) may, within fifteen days from the date of communication from the Board, submit the complete and revised application that conforms to the requirements of these regulations:
- Provided that no further opportunity shall be given to the applicant to make an application in respect of the alleged default at the same stage of the proceedings, as indicated in Table I in Schedule-II.
- (7) Where the applicant is an association or a firm or a body corporate or a limited liability partnership, the application and undertakings and waivers shall be executed by the person in charge of, and responsible for the conduct of the business of such firm or association or body corporate and the same shall bind the firm or association, the body corporate and any officer who is in default.



**Explanation.** - For the purpose of this sub-regulation, the expression 'officer who is in default' shall have the same meaning as provided in sub-Section (60) of Section 2 of the Companies Act, 2013.

(8) An application for settlement of defaults related to disclosures, shall to the extent possible, be made after making the required disclosure.

**Limitation**

4. (1) An application in respect of any specified proceeding pending before the Board shall not be considered if it is made after sixty days from the date of service of the notice to show cause or supplementary notice(s) to show cause, whichever is later.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Board may consider the application, if satisfied that there was sufficient cause for not filing it within the specified period and it is accompanied with non-refundable fees as specified in Part-B of the Schedule-I:

Provided that, where the application is filed after sixty calendar days from the expiry of the period specified in sub-regulation (1), the settlement amount determined in accordance with Schedule-II of these regulations shall be increased by twenty five percent:

Provided further that, no such delayed application shall be considered if the application is filed after one hundred and twenty calendar days from the expiry of the period specified in sub-regulation (1) or after the first hearing, whichever is earlier.

(3) The provisions of this regulation shall not apply in the case of proceedings pending before the Tribunal or any court.

### CHAPTER III

#### SCOPE OF SETTLEMENT

**Scope of settlement proceedings**

5. (1) No application for settlement of any specified proceedings shall be considered, if:

- (a) an earlier application with regard to the same alleged default had been rejected;
- (b) the audit or investigation or inspection or inquiry, if any, in respect of any cause of action, is not complete, except in case of applications involving confidentiality; or
- (c) monies due under an order issued under securities laws are liable for recovery under securities laws.

(2) The Board may not settle any specified proceeding, if it is of the opinion that the alleged default, -

- i. has market wide impact,
- ii. caused losses to a large number of investors, or
- iii. affected the integrity of the market.

(3) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, for settling any specified proceeding the Board may *inter alia* take into account the following factors, -

- (a) whether the applicant has refunded or disgorged the monies due, to the satisfaction of the Board;
- (b) whether the applicant has provided an exit or purchase option to investors in compliance with securities laws, to the satisfaction of the Board;
- (c) whether the applicant is in compliance with securities laws or any order or direction passed under securities laws, to the satisfaction of the Board;
- (d) any other factor as may be deemed appropriate by the Board.

(4) Without prejudice to sub-regulations (1) and (3), the Board may not settle the specified proceedings where the applicant is a wilful defaulter, a fugitive economic offender or has defaulted in payment of any fees due or penalty imposed under securities laws.

(5) Nothing contained in these regulations shall be construed to restrict the right of the Panel of Whole Time Members to consider or reject any application in respect of any specified proceeding without examination by the Internal Committee or the High Powered Advisory Committee.

**Rejection of application**

6. (1) An application may at any time be rejected on the following grounds:

- (a) Where the applicant refuses to receive or respond to the communications sent by the Board;
- (b) Where the applicant does not submit or delays the submission of information, document, etc., as called for by the Board;
- (c) Where the applicant who is required to appear, does not appear before the Internal Committee on more than one occasion;
- (d) Where the applicant violates in any manner the undertaking and waivers as provided in Part-C of the Schedule-I;
- (e) Where the applicant does not remit the settlement amount within the period specified in clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 15 and/or does not abide by the undertaking and waivers.

(2) The rejection under sub-regulation (1) shall be communicated to the applicant:

Provided that the applicant shall continue to be bound by the waivers given in respect of limitation or laches in respect of the initiation or continuation or restoration of any legal proceeding and the waivers given under sub-para (d), (e), (f) and (g) of para 12 of the undertaking and waivers as provided in Part-C of the Schedule-I.

**Withdrawal of application**

7. (1) An application may be withdrawn at any time prior to the communication of the decision of the Panel of Whole Time Members under regulation 15.

(2) An applicant who withdraws an application under sub-regulation (1) shall not be permitted to make another application in respect of the same default:

Provided that, as may be recommended by the High Powered Advisory Committee, such an application may be considered subject to an increase of at least fifty percent over the settlement amount determined in accordance with Schedule-II of these Regulations.

**Effect of pending application on specified proceedings**

8. (1) The filing of an application for settlement of any specified proceedings shall not affect the continuance of the proceedings save that the passing of the final order shall be kept in abeyance till the application is disposed of.

(2) Where the application is filed in case of proceedings that may be initiated against the applicant, such proceedings shall not be initiated till the application is rejected or withdrawn:

Provided that, the filing of an application shall not prohibit the initiation of any proceedings, in so far as may be deemed necessary for the purpose of issuance of interim civil and administrative directions to protect the interests of investors and to maintain the integrity of the securities markets.

**Explanation.** - Where any proceeding is pending or to be initiated against several persons but the settlement application is filed only by one or more persons, but not all, the filing of such an application shall not affect the initiation, continuation and disposal of the proceedings against the person who has not filed the application for settlement and any adverse observations made in such proceedings against the applicant shall qua the applicant be subject to the outcome of the settlement application filed by such applicant.

**CHAPTER IV****TERMS OF SETTLEMENT****Settlement terms**

9. (1) The settlement terms may include a settlement amount and/or non-monetary terms, in accordance with the guidelines specified in Schedule-II.

(2) The non-monetary terms may include the following:

- (a) Suspension or cessation of business activities for a specified period;
- (b) Exit from Management;
- (c) Disgorgement on account of the action or inaction of the applicant;
- (d) Refraining from acting as a partner or officer or director of an intermediary or as an officer or director of a company that has a class of securities regulated by the Board, for specified periods;
- (e) Cancel securities and reduce holdings where the securities are issued fraudulently, including bonus shares received on such securities, if any, and reimburse any dividends received, etc.;
- (f) Lock-in of securities;
- (g) Implementation of enhanced policies and procedures to prevent future securities laws violations as well as agreeing to appoint or engage an independent consultant to review internal policies, processes and procedures;
- (h) Provide enhanced training and education to employees of intermediaries and securities market infrastructure institutions;
- (i) Submit to enhanced internal audit and reporting requirements.

(3) The settlement amount, excluding the legal costs and disgorged amount, shall be credited to the Consolidated Fund of India.

(4) The application fee referred to in sub-regulation (2) of regulation 3 and the legal costs, if any, forming part of the settlement amount shall be credited to the Securities and Exchange Board of India General Fund.

**Explanation.** – Legal costs shall include liquidated costs, as may be determined by the Board, in respect of costs for obtaining appropriate orders from the Tribunal or Court under sub-regulation (2) of regulation 24.

(5) The amount of profits made or losses avoided by the applicant that may be disgorged as part of the settlement terms, shall be credited to the Investor Protection and Education Fund.

**Factors to be considered to arrive at the settlement terms**

**10.** While arriving at the settlement terms, the factors indicated in Schedule-II may be considered, including but not limited, to the following:

- (a) conduct of the applicant during the specified proceeding, investigation, inspection or audit;
- (b) the role played by the applicant in case the alleged default is committed by a group of persons;
- (c) nature, gravity and impact of alleged defaults;
- (d) whether any other proceeding against the applicant for non-compliance of securities laws is pending or concluded;
- (e) the extent of harm and/or loss to the investors' and/or gains made by the applicant;
- (f) processes that have been introduced since the alleged default to minimize future defaults or lapses;
- (g) compliance schedule proposed by the applicant;
- (h) economic benefits accruing to any person from the non-compliance or delayed compliance;
- (i) conditions which are necessary to deter future non-compliance by the same or another person;
- (j) satisfaction of claim of investors regarding payment of money due to them or delivery of securities to them;
- (k) any other enforcement action that has been taken against the applicant for the same violation;
- (l) any other factors necessary in the facts and circumstances of the case.

## **CHAPTER V COMMITTEES**

**High Powered Advisory Committee**

**11.** (1) The Board shall constitute a High Powered Advisory Committee for consideration and recommendation of the terms of settlement.

(2) The High Powered Advisory Committee shall consist of a Judicial member who has been the Judge of the Supreme Court or a High Court and three external experts having expertise in securities market or in matters connected therewith or incidental thereto.

(3) The term of the members of the High Powered Advisory Committee shall be three years which may be extended for a further period of two years.

(4) The quorum for a meeting of the High Powered Advisory Committee shall be of three members.

**Explanation.** - Meeting includes meeting through audio-video electronic means or through the medium of electronic video linkage.

(5) The High Powered Advisory Committee shall conduct its meetings in the manner specified by the Board in this regard:

Provided that:

- (i) where any member of the High Powered Advisory Committee seeks recusal, the remaining two or more members may submit their recommendation on the terms of settlement;
- (ii) where no consensus or majority may be reached, the recommendation made by the Judicial member shall be considered to be the recommendation of the High Powered Advisory Committee and in case of recusal of the Judicial member, the recommendations of the remaining two or more members shall be submitted for consideration to the Panel of Whole Time Members; and
- (iii) where all or all but one of the members of the High Powered Advisory Committee recuse themselves in respect of an application, the Board may constitute another High Powered Advisory Committee.

**Internal committee(s)**

12. (1) Internal Committee(s) shall be constituted by the Board.

(2) The Internal Committee(s) shall comprise of an officer of the Board not below the rank of Chief General Manager and such other officers as may be specified by the Board.

**CHAPTER VI****PROCEDURE OF SETTLEMENT****Proceedings before the Internal Committee**

13. (1) Save as otherwise provided in these regulations, an application shall be referred to an Internal Committee to examine whether the proceedings may be settled and if so to determine the settlement terms in accordance with these regulations.

(2) The Internal Committee may:

- (a) call for relevant information, documents, etc., pertaining to the alleged default(s) in possession of the applicant or obtainable by the applicant;

**Explanation.** – Nothing in these regulations shall confer a right upon the applicant to seek information from the Board or require the Board to seek information from any other person for the purpose of relying upon it in the settlement proceedings or request the Board to permit it to present information not already disclosed in the application, which the applicant was aware of at the time of making the application or which information upon diligent enquiry being made could have become known to the applicant.

- (b) call for the personal appearance of the applicant before it:

Provided that a duly authorized representative of the applicant may represent on behalf of the applicant:

**Explanation.** - Personal appearance under this clause includes appearance through audio-video electronic means or through the medium of electronic video linkage as may be permitted by the Internal Committee.

- (c) permit the applicant to submit revised settlement terms within a period not exceeding ten working days from the date of the Internal Committee meeting:

Provided that the revised settlement terms received after ten working days, but within twenty working days may be considered subject to an increase of ten percent over the recommended settlement amount.

(3) The proposed settlement terms, if any, shall be placed before the High Powered Advisory Committee.

**Proceedings before the High Powered Advisory Committee**

14. (1) The High Powered Advisory Committee shall consider the proposed settlement terms placed before it along with the following:

- (a) the application, undertaking and waivers of the applicant;
- (b) factors specified in regulation 10;
- (c) settlement terms or revised settlement terms proposed by the applicant;
- (d) any other relevant material available on record.

(2) The High Powered Advisory Committee may seek revision of the settlement terms and refer the application back to the Internal Committee.

(3) The recommendations of the High Powered Advisory Committee shall be placed before the Panel of Whole Time Members.

**Action on the recommendation of High Powered Advisory Committee**

**15.** (1) The Panel of Whole Time Members shall consider the recommendations of the High Powered Advisory Committee and may accept or reject the same:

Provided that where the recommendations of the High Powered Advisory Committee to settle the specified proceedings are rejected, the panel of Whole Time Members shall record reasons for rejection of the recommendations :

Provided further that where the recommendation of the High Powered Advisory Committee to settle the specified proceedings are rejected, such decision of the panel of Whole Time Members shall be communicated to the applicant.

(2) Where the Panel of Whole Time Members accepts the recommendation of the High Powered Advisory Committee to settle the specified proceedings, the applicant shall be issued a notice of demand within seven working days of the decision of the panel and the applicant shall, -

(a) remit the settlement amount forming part of the settlement terms, not later than fifteen calendar days from the date of receipt of the notice of demand, which may be extended by the Panel of Whole Time Members for reasons to be recorded, by fifteen calendar days:

**Explanation.** – Remittance of settlement amount shall be done by way of a demand draft drawn in favour of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai or by way of direct credit in the specified bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other authorised mode of payment:

Provided that, where the settlement amount is remitted after thirty calendar days from the date of receipt of the notice of demand and on or before the ninetieth day from such receipt, the settlement amount payable by the applicant shall be increased by the levy of simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of receipt of the notice of demand till the date of payment of the settlement amount:

Provided further that, in no case shall such remittance be accepted after the ninetieth calendar day from the date of the receipt of the notice of demand.

(b) fulfil/undertake in writing to abide by, the other settlement terms, if any, within the time provided to the applicant.

(3) Where the Panel of Whole Time Members does not accept the recommendation of the High Powered Advisory Committee to settle the specified proceedings on the settlement terms recommended by it, the panel may return the application for re-examination of the settlement terms and thereafter the procedure as applicable in the case of an original application shall be followed by the Internal Committee and the High Powered Advisory Committee.

**CHAPTER VII****SUMMARY SETTLEMENT PROCEDURE****Summary settlement procedure**

**16.** (1) Notwithstanding anything contained in Chapter VI, before initiating any specified proceeding, the Board may issue a notice of summary settlement in the format as specified in Part-A of Schedule-III, calling upon the noticee to file a settlement application under Chapter-II and submit the settlement amount and/or furnish an undertaking in respect of other non-monetary terms or comply with other non-monetary terms, as may be specified in the summary settlement notice in respect of the specified proceeding(s) to be initiated for the following defaults,-

- i. Delayed disclosures, including filing of returns, report, document, etc.;
- ii. Non-disclosure in relation to companies exclusively listed on regional stock exchanges which have exited;
- iii. Disclosures not made in the specified formats;
- iv. Delayed compliance of any of the requirements of law or directions issued by the Board;
- v. Such other defaults as may be determined by the Board:

Provided that, the specified proceeding(s) shall not be settled under this Chapter, if in the opinion of the Board, the applicant has failed to make a full and true disclosure of facts or failed to co-operate in the required manner.

(2) Notwithstanding anything contained in the notice of settlement, the Board shall have the power to modify the enforcement action to be brought against the noticee and the notice of settlement shall not confer any right upon the noticee to seek settlement or avoid any enforcement action.

(3) The noticee may, within thirty calendar days from the date of receipt of the notice of settlement, -

- (a) file a settlement application in the Form specified in Part-A of Schedule-I along with non-refundable application fee as specified in Part-B and the undertakings and waivers as specified in Part-C of Schedule-I;

- (b) remit the settlement amount as specified in the notice of settlement;
- (c) comply or undertake to comply with other non-monetary terms as specified in the notice of settlement, as the case may be; and
- (d) seek rectification of the calculation of the settlement amount, as communicated in the notice of settlement, at the time of filing the settlement application and in all such cases, the decision of the Board shall be final and remittance shall be done within thirty calendar days from the date of receipt of the decision of the Board:

Provided that, the Board may for reasons to be recorded, grant extension of time not exceeding a further period of fifteen calendar days for filing the settlement application, remittance of the settlement amount and/or furnishing an undertaking in respect of any of the non-monetary terms or compliance with any of the non-monetary terms specified in the notice of settlement.

- (4) Upon being satisfied with the remittance of settlement amount and undertaking furnished in respect of the non-monetary terms or compliance with non-monetary terms, if any as detailed in the settlement notice, the Board shall pass an order of settlement under regulation 23.

17. Notwithstanding anything contained in these regulations, where a noticee does not file a settlement application under this Chapter or remit the settlement amount and/or comply with other non-monetary terms to the satisfaction of the Board or withdraws the settlement application at any time prior to the communication of the decision of the Board, the specified proceedings may be initiated, and such a noticee shall only be permitted to file a settlement application in respect of the proceedings pending before the Court or Tribunal, after conclusion of proceedings before the Adjudicating Officer or the Board, as the case may be.

## **CHAPTER VIII**

### **SETTLEMENT NOTICE**

#### **Settlement notice**

18. (1) A notice of settlement in the format as specified in Part-B of Schedule-III, indicating the substance of the probable charges and enforcement actions, may, except in cases covered under Chapter VII, be issued by the Board prior to the issuance of the notice to show cause so as to afford the noticee an opportunity to file a settlement application under Chapter-II, within fifteen calendar days from the date of receipt of the settlement notice.

(2) Notwithstanding anything contained in the settlement notice, the Board shall have the right to modify the nature of the enforcement action to be initiated against the noticee and the charges stated in the notice shall not confer any right to seek settlement on the said basis or avoid any enforcement action due to modified charges.

(3) Where a noticee does not file the settlement application under this Chapter or withdraws the settlement application at any time prior to the communication of the decision of the Panel of Whole Time Members under regulation 15, the specified proceedings may be initiated and such a noticee shall only be permitted to file a settlement application in respect of the proceedings pending before a Court or tribunal, after conclusion of the proceedings before the Adjudicating Officer or the Board, as the case may be.

## **CHAPTER IX**

### **SETTLEMENT WITH CONFIDENTIALITY**

#### **Settlement with confidentiality**

19. (1) An applicant seeking the benefit of confidentiality in return for admitting for the limited purpose of settlement of specified proceedings to be initiated and agreeing to provide substantial assistance in the investigation, inspection, inquiry or audit, to be initiated or ongoing, against any other person in respect of a violation of securities laws, shall fulfil the conditions of this Chapter, including –

- (a) cease to participate in the violation of securities laws from the time of the disclosure of information, unless otherwise directed by the Board;

- (b) provide and continue to provide complete and true disclosure of information, documents and evidence, which is in his possession or he is able to obtain, to the satisfaction of the Board in respect of the alleged contravention of the provisions of securities laws;
- (c) co-operate fully, continuously and expeditiously throughout the investigation, inspection, inquiry or audit and related proceedings before the Board; and
- (d) not conceal, destroy, manipulate or remove the relevant documents in any manner that may contribute to the establishment of the alleged violation.

**Explanation.** – Violation of securities laws in this Chapter refers to defaults other than those of disclosure and reporting requirements detailed in Schedule II:

Provided that an application made under this chapter shall be made only in cases prior to or pending investigation, inspection, inquiry or audit.

- (2) Notwithstanding anything contained in this Chapter, where an applicant fails to comply with the conditions mentioned in this regulation, the Board may rely upon the information and evidence submitted by the applicant in any proceedings.
- (3) Without prejudice to sub-regulations (1) and (2), the Board may subject the applicant to further restrictions or conditions, as deemed fit, after considering the facts and circumstances of the case.
- (4) For the purpose of seeking confidentiality, the applicant or its authorized representative may make an application containing all the relevant disclosures pertaining to the information as specified in Schedule-IV for furnishing the information and evidence relating to the commission of any violation of securities laws.
- (5) Upon being satisfied the Board may assure the benefit of confidentiality and shall thereupon mark the status of the application depending upon its priority and convey the same to the applicant in writing.
- (6) The Board may, for reasons to be recorded in writing, at any stage, reject the application if the information, documents or evidence is found to be incomplete or false to the knowledge of the applicant.
- (7) The rejection of the application for confidentiality shall be communicated to the applicant.

#### **Procedure**

**20.** (1) The provisions of Chapters IV to VI of these regulations may be applied *mutatis mutandis* to a settlement application filed under this Chapter and a settlement order passed accordingly.

(2) The information, documents and evidence provided by the applicant under this chapter shall be submitted in the manner specified by the Board.

#### **Confidentiality and assurance**

**21.** For the purposes of providing the applicant with interim confidentiality and assurance from being proceeded with, the Board may not initiate regulatory measures when the Board has a reasonable belief that the information provided to it relates to a possible securities law violation that has occurred, is ongoing or about to occur.

#### **Confidentiality**

**22.** Notwithstanding anything contained in Chapter X, the following shall be treated as confidential, -

- (a) the identity of the applicant seeking confidentiality; and
- (b) the information, documents and evidence furnished by the applicant under this Chapter:

Provided that, the identity of the applicant or such information or documents or evidence may not be treated as confidential if, —

- (i) the disclosure is required by law;
- (ii) the applicant has agreed to such disclosure in writing; or
- (iii) there has been a public disclosure by the applicant.

## CHAPTER X

### SETTLEMENT ORDERS

#### **Settlement of proceedings before the Adjudicating Officer and the Board**

**23.** (1) The Adjudicating Officer shall by an appropriate order dispose of the proceeding pending before him on the basis of the approved settlement terms.

**Explanation.** -In case of concurrent proceedings, a comprehensive order may be passed by the Panel of Whole Time Members and thereafter the concerned Adjudicating officer may pass an order, disposing of the relevant proceedings before him, in view of the settlement.

(2) The Panel of the Whole Time Members shall by an appropriate order dispose of proceedings initiated or proposed to be initiated other than the proceedings referred to in sub-regulation (1).

(3) The settlement order passed under these regulations shall, contain the details of the alleged default(s), relevant provisions of the securities laws, brief facts and circumstances relevant to the alleged default, the admissions made by the applicant, if any and the settlement terms.

#### **Settlement of the proceedings pending before the Tribunal or any court**

**24.** (1) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions with regard to settlement of specified proceedings shall *mutatis mutandis* apply to an application for settlement of any proceeding pending before the Tribunal or any court.

(2) The proposal of settlement along with the settlement terms or rejection thereof shall be placed before such Tribunal or court for appropriate orders.

#### **Service and publication of settlement order**

**25.** Settlement orders shall be served on the applicant and shall also be published on the website of the Board:

Provided that settlement orders in matters relating to the confidentiality shall not, directly or indirectly, disclose the identity of the applicant, but shall indicate the provisions of securities laws which the applicant is alleged to have violated.

#### **Settlement Schemes**

**26.** Notwithstanding anything contained in these regulations, the Board may specify the procedure and terms of settlement of specified proceedings under a settlement scheme for any class of persons involved in respect of any similar specified defaults.

**Explanation.** - A settlement order issued under a Settlement scheme shall be deemed to be a settlement order under these regulations.

#### **Effect of settlement order on third party rights or other proceedings**

**27.** (1) A settlement order under these regulations shall not be admissible as evidence in any other proceeding relating to an alleged default not covered under the settlement order nor affect the right of third parties arising out of the alleged default.

(2) Where any applicant who obtains a settlement order is also noticee along with any other person in any civil and administrative proceeding, the Adjudicating Officer or the Board while disposing proceedings against such other person may make necessary observations in respect of the applicant in so far as is necessary to prove the act of another:

Provided that, unless the settlement order is revoked, such observations shall qua the applicant be subject to the settlement order obtained by the applicant.

(3) Where any person has obtained a settlement order, which contains observations in respect of any other person for the commission of an alleged default, such an order shall not in itself be admissible as evidence against such other person.



**Revocation of the settlement order**

28. (1) If the applicant fails to comply with the settlement order or at any time after the settlement order is passed, it comes to the notice of the Board that the applicant has not made full and true disclosure or has violated the undertakings or waivers, settlement order shall stand revoked and withdrawn and the Board shall restore or initiate the proceedings, with respect to which the settlement order was passed.

(2) Whenever any settlement order is revoked, no amount paid under these regulations shall be refunded.

## CHAPTER XI MISCELLANEOUS

**Confidentiality of information**

29. (1) All information submitted and discussions held in pursuance of the settlement proceedings under these regulations shall be deemed to have been received or made in a fiduciary capacity and the same may not be released to the public, if the same prejudices the Board and/or the applicant.

(2) Where an application is rejected or withdrawn, the applicant and the Board shall not rely upon or introduce as evidence before any court or Tribunal, any proposals made or information submitted or representation made by the applicant under these regulations:

Provided that this sub-regulation shall not apply where the settlement order is revoked or withdrawn under these regulations.

**Explanation.** – When any fact is discovered in consequence of information received from a person in pursuance of an application, so much of such information, whether it amounts to an admission or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved.

**Power to remove difficulties**

30. In order to remove any difficulty in the interpretation or application or implementation of the provisions of these regulations, the Board shall have the power to issue clarifications and specify procedures through circulars or guidelines.

**Irregularity in procedure**

31. No settlement order or rejection of a settlement application shall be void on ground of any defect in procedure or calculation of the settlement amount or on account of any vacancy in or any defect in the constitution of any committee under Chapter V:

Provided that, nothing in these regulations shall prohibit the Board from revoking the settlement order where the applicant fails to pay any difference due to any discrepancy in calculation of the settlement amount:

Provided further that, the applicant shall continue to be bound by the waivers given in respect of limitation or laches in respect of initiating or continuing or restoring of any legal proceeding and the waivers given in sub-paras (d), (e) (f) and (g) of para 12 of the undertaking and waivers as provided in Part-C of the Schedule-I.

**Relevance of these regulations in specified proceedings**

32. Schedule-II of these regulations shall be relevant but not bind the Board or an Adjudicating Officer in any specified proceeding and the Board or the Adjudicating Officer may apply them to the extent possible.

**Procedure for composition**

33. The provisions of Chapters IV to VI and Schedule-II may be applied *mutatis mutandis* for arriving at a proposal pursuant to a compounding application.

**Repeal and savings**

**34.** (1) On and from the commencement of these regulations, Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 shall stand repealed.

(2) Notwithstanding any such repeal:

(a) Notice of settlement issued under the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 shall be deemed to have been filed in accordance with these regulations and shall be dealt with in accordance with the provisions of these regulations;

(b) All applications filed under the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 and pending with the Board shall be deemed to have been filed in accordance with these regulations and shall be dealt with in accordance with the provisions of these regulations;

(c) All settlement orders passed under the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 shall be deemed to have been passed under these regulations;

(d) The Internal Committee(s) and the High Powered Advisory Committee constituted by the Board in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014, shall be deemed to have been constituted under these regulations;

(e) The proposals of the Internal Committees and the recommendations of the High Powered Advisory Committee in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 and any action taken by the Board on the basis of these recommendations shall be deemed to have been made under these regulations.

(3) Notwithstanding anything contained in Chapters VI to Chapter VIII, with respect to specified proceedings pending as on the date of commencement of this Chapter, the Board may issue a notice of summary settlement or settlement under Chapter VII or Chapter VIII, as the case may be, in respect of such proceedings and in such cases the procedure specified in Chapter VII or Chapter VIII shall apply *mutatis mutandis*, as the case may be:

*Explanation.* -For the purposes of this sub-regulation, it is clarified that a specified proceeding is not deemed to be initiated and pending, unless the Board has communicated the matter to the authority who shall conduct such proceedings.

**SCHEDULE-I**

(See regulation 3)

**Part-A****FORM****Application for settlement**

**(To be filed only after conclusion of investigation, inspection, inquiry or audit, as the case may be)**

(For Office use only)

Date of receipt of the application:

Application Registration Number:

*(Instructions: All particulars, including submission regarding details of loss caused to investors, profit made and proposed settlement amount **must** be filled, else application shall be returned. Put 'NA' only where NOT APPLICABLE.)*

**Before the Securities and Exchange Board of India**

In the matter of .....

1. Name/Trade name of the applicant/co-applicants:
    - (a) Registration no., if applicable :
    - (b) Date of Registration, if applicable :
    - (c) PAN/DIN/CIN number, as available:
    - (d) Paid-up capital of applicant:
  2. If stock broker, name of the stock exchange:
  3. If sub-broker/authorised person, name of stock broker with whom affiliated and name of the stock exchange:
  4. Name of the segment (Cash/derivative etc.):
  5. Form of organization: corporate body/ sole proprietorship / partnership / LLP/ financial institution (if listed co., details of listing):
  6. Names of promoters/directors/proprietors/partners:
  7. Key management personnel(s):
  8. Address/correspondence address, contact no./fax no. and email (any changes in aforesaid details shall be communicated to the Board promptly):
  9. Name and contact details (including e-mail) of the contact person (s):
  10. Other registration(s) with the Board, if applicable:
    - (a) Trade name :
    - (b) Registration type :
    - (c) Registration no. :
  11. Case(s) pending with the Board/SAT/Court (Pl. specify):
  12. Case(s) pending under 11B/Adjudication/Enquiry/others (pl. specify):
  13. Stage at which pending:
  14. Interim order(s) in the pending proceedings (gist of the orders passed), if any:
  15. Other actions pending with/concluded by the Board, if any (with their details):
    - (a) Against the applicant :
    - (b) Against its associates :
    - (c) Against its key management personnel(s) :
    - (d) Against its other promoters/directors:
    - (e) Other details, if any:
  16. Date of show cause notice/summons/communication indicating probable cause of action, if any, against which the settlement is sought (PLEASE ENCLOSE COPIES)\*:
  17. Full and true disclosure of facts (including the loss caused, profit made, loss avoided, gross fees, brokerage, commissions, etc., in respect of the cause of action, with manner of calculation thereof):
- [APPLICANT TO TAKE INTO ACCOUNT THE GUIDELINES PROVIDED IN SCHEDULE-II]
18. Specific charges alleged:
  19. Submissions in respect of sub-regulations (2), (3) & (4) of Regulation 5:
  20. Terms of settlement proposed by the Applicant:-
    - (a) Monetary terms, with manner of calculation:-
    - (b) Non-monetary terms, including manner of calculation of terms of disgorgement due:-

21. Original documents to be enclosed:
  - (a) Undertakings and waivers (as per Format specified in Part C).
  - (b) Authority letter/Board resolution.
22. List of other enclosures:
  - (a) A copy of the notice to show cause/summons/communication/other notices indicating the probable cause of action, if any, against which the settlement is sought;
  - (b) Complete Annual Reports / other relevant financial details for the last three financial years and the quarterly audited financial results of the current year;
  - (c) A statement showing net worth of the applicant (only for those applicants who are required to comply with the networth requirements as specified by the Board or by the stock exchanges), gross annual income before tax, the amount of gross profit made/loss avoided, including the gross brokerage, fees, management/performance/transaction fee, carried interest, compensation, etc., in respect of the said default;
  - (d) Copy of PAN card/ DIN/CIN details;
  - (e) Complete Income-tax Returns of the applicant for the last three financial years;
  - (f) In case of a foreign body corporate applicant, include details relating to incorporation, place of business, registration details with any non-Indian financial sector regulatory authority.
  - (g) In case of a non-resident applicant, include details relating to passport and national identity document, if any.
  - (h) Any other relevant document (s)/submissions.

(Signature of the applicant)

(Stamp and Seal of body corporate applicant)

### **Verification**

I, .....son/daughter/wife of (Name in block letters)

Shri .....being the applicant/authorised representative (in case of body corporate) of ..... do hereby verify and affirm on oath that this application and the contents thereof are true to my knowledge and belief and as per the records and that I have not suppressed any material facts and shall keep the Board informed without delay, of any other relevant information that may come to my notice.

(Signature of the applicant)

Date:

Place :

### **Part-B**

Every applicant under Chapter II of these regulations shall pay a non-refundable processing fee of fifteen thousand rupees, by way of a demand draft in favour of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai or by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by RBI.

Provided that, where the applicant is a body corporate, the non-refundable processing fee shall be Twenty-five thousand rupees.

**Part-C**  
**Undertakings and Waivers**

Format

Undertaking to be submitted by each applicant, along with the application with stamp duty duly paid and duly notarized at the time of execution.

I/We, ....., the applicant(s) herein, as a condition for making the enclosed application to the Board for examining and consideration of the application, hereby declare that I/we agree and undertake that:

- (1) I/We admit the jurisdiction and right of the Securities and Exchange Board of India to initiate appropriate proceedings in respect of the alleged default.
- (2) I/We further agree and undertake that the time spent during the settlement proceedings shall be excluded for computing the limitation period or laches, if any, for initiating or continuing or restoring any legal proceedings, if any, against me/us, and waive any objections in this regard.
- (3) The Securities and Exchange Board of India may enforce any claims against me/us arising from or/in relation to any violation of the settlement order passed pursuant to this application.
- (4) Nothing in the settlement order shall preclude any other person from pursuing any other legal remedy to which such person may be entitled against me/us as per law.
- (5) The settlement proposed by me/us does not limit or create any private rights or remedies for any person who is not a party to these proceedings, against me/us.
- (6) The settlement amount including legal costs, if any, shall be paid by me/us to the Board within the period stipulated by the Board.
- (7) The settlement order shall be construed and enforced in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, as amended from time to time.
- (8) I/We agree that subsequent to the passing of the settlement order, I/We shall not take any action or make or permit to be made any public statement denying, directly or indirectly, any finding of the Board including that recorded in the settlement order or creating impression that the settlement order is without factual basis.
- (9) I/We hereby declare that nothing in the waiver and undertaking given by me/us shall affect my/our (i) testimonial obligations, or (ii) right to take legal or factual positions in defence of litigation or in defense of a claim or in any other legal proceeding in which the Board is not a party.
- (10) I/We for the limited purpose of settlement under these regulations 'admit the findings of fact and conclusions of law' or 'neither admit nor deny the findings of fact and conclusions of law' (strike off whichever is not applicable), and agree to abide by the settlement order as may be passed in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 and guidelines and circulars issued by the Board in that regard:  

Provided that, in relation to defaults related to disclosures other than relating to a prospectus or a letter of offer or a similar such document required to be made in relation to an issue of securities, I/we do not deny the alleged default.
- (11) I/We waive my/our right of taking any legal proceedings against the Securities and Exchange Board of India concerning any of the issue covered in the settlement order that may be passed.

(12) I/We further waive the following:

- (a) the findings of fact and conclusions of law;
- (b) the proceedings before the Board or any officer of the Board;
- (c) the right to all post-hearing procedures;
- (d) appeal/review before the Tribunal/courts;
- (e) any plea relating to such provisions of the regulations or other requirements of law, including conflict of interest, as may be construed to prevent any member or officer of the Securities and Exchange Board of India from participating in the proceedings, including settlement proceedings or assisting or advising the Internal Committee, High Powered Advisory Committee or Panel of Whole Time Members, as to, any order, opinion, finding of fact, or conclusion of law, etc.;
- (f) any plea of bias or pre-judgment by the Securities and Exchange Board of India, the officers or the High Powered Advisory Committee, based on the consideration of or discussions concerning settlement of all or any part of the internal proceedings; and
- (g) any plea of limitation or laches for initiating or restoring of the proceedings, if the applicant violates the settlement order.

(13) I/We undertake as a condition of settlement to not seek, directly or indirectly, any set-off, reimbursement by way of indemnification, insurance coverage or any other form of non-tax reimbursement.

(Signature of the applicant with stamp and seal of the body corporate)

Before me.

Notary.

## SCHEDULE-II

(See regulation 10)

### CHAPTER I

#### GUIDELINES FOR ARRIVING AT SETTLEMENT TERMS

1. The settlement amount (SA) *shall* comprise of the Indicative Amount (IA) arrived at in terms of these guidelines and the factors provided in regulation 10, wherever applicable.
2. The IA shall not be less than Rupees 3 lakh for first time applicants or Rupees 7 lakh for others, as the case may be:

Provided that in case of individual applicants who submit to the satisfaction of the IC or HPAC or Panel of WTM's that, without knowledge of the illegal activity, they had lent the use of their securities account to the key operator or intermediary or securities market infrastructure institution involved in such activity, the SA may not exceed the minimum penalty for that violation under securities laws.

*Explanation.*-A 'first time applicant' is a person against whom no order has been passed by the adjudicating officer or by the Board or who has never obtained a settlement order from the Board as on the date of the present application.

3. Based on the stage at which the proceeding(s), for which the application is made, is/are pending, the proceeding conversion factor (PCF) shall be applied when calculating the IA.
4. In cases, where an existing business or activity of a person is either corporatized or converted into an LLP or partnership or merged or taken over by a new management, the existing record of the erstwhile entity shall be deemed to be the record of the new entity. Considerations including insolvency, change of name or management

or ownership, etc., shall be considered in accordance with the guidelines issued by the Board, if any, from time to time.

5. PCF for Applications made voluntary or seeking settlement with confidentiality: Where an entity desires to obtain the benefit of a lower PCF, it may, *suo motto*, before the receipt of any notice to show cause, intimate the Board of such default hereinafter referred to as 'intimation defaults' and co-operate with the Board in the investigation, inquiry, inspection or audit. Such an application shall be deemed to have been made 'Pre- issue of notice to show cause' for the purpose of calculating the PCF.
6. The IA shall be calculated per count of default, jointly or separately as per the facts and circumstances of the case, in accordance with these guidelines.
7. While considering the application, the alleged default(s) detailed in the Inspection Report or the Investigation Report or the Report of the Designated Authority (DA) or the notice to show cause, including any supplementary notice to show cause issued by any authority in a pending proceeding, or the facts/findings detailed in the order of the Designated Member (DM) or the Whole Time Member (WTM) or the Adjudicating Officer (AO) or the Securities Appellate Tribunal (SAT), as applicable, may be the basis for calculating the IA.

In case, the Internal Committee (IC) or the High Powered Advisory Committee (HPAC) or the Panel of Whole Time Members (WTMs) are of the opinion that the facts disclose a different default, the modification of the charge(s) may be sought.

8. The alleged defaults shall, wherever applicable, be categorised based on the facts and circumstances by the IC or HPAC or the Panel of WTMs.
9. Notwithstanding anything contained in these guidelines, the IC or HPAC or Panel of WTMs shall have the discretion to recommend acceptance or rejection or accept or reject an application, to recommend an amount, lower or higher than the amounts arrived at in terms of these guidelines, for reasons to be recorded, in accordance with the provisions of securities laws, considering the facts and circumstances of the case and the gravity of the charges.
10. In case the applicant is body corporate, the IC or HPAC or Panel of WTMs may require that the SA payable by a body corporate is to be paid by the officers in default including the persons in charge of the body corporate to avoid burdening investors holding securities issued by the body corporate:  
**Explanation.** – The principle in clause 10 may be applied *mutatis mutandis* to the sponsor, manager, or trustee (by whatever name called) of a trust, the karta of a Hindu Undivided Family, the office bearers of an association of persons, as the case may be.
11. In cases where the formulae for calculating the IA are inapplicable or cannot be adapted due to the peculiar nature of the default or the facts and circumstances of the case or where the defaults detailed in the Tables in these guidelines are not covered, the IC or HPAC or Panel of WTMs may arrive at the SA, as they deem fit.
12. In case of an amendment(s) or repeal of the securities laws, these guidelines shall continue to apply to similar provisions under the amended or new laws, *mutatis mutandis*.

## Chapter II

### INDICATIVE AMOUNT AND THE SETTLEMENT AMOUNT

Indicative amount (IA) shall be calculated as follows:

$$IA = A \times B + \text{Legal Costs}^{\#}$$

**#Legal costs of the Board may be applicable to an application made at the stages mentioned in points “b”, “d” and “e” as provided in Table I.**

Where:

$$\text{'A'} = \text{PCF} + \text{RAF}$$

**A:** Multiplying Factor.

**PCF:** Proceeding Conversion Factor.

**RAF:** Regulatory Action Factor.

$$\text{'B'} = \text{BV} \times \text{BA}$$

**B:** *Applicable Benchmark Amount*, is the amount attributable to every count of the alleged default in accordance with these guidelines;

**'BV':** Aggregate of the base values given to the relevant factors including the aggravating and mitigating factors in respect of a particular charge.

**'BA':** Base amount attributable to every count of the alleged default in accordance with these guidelines.

1. The IA shall not exceed the maximum penalty under securities laws that may be levied for each count of violation multiplied by the counts of alleged default in accordance with these guidelines.
2. (a) Where an order of penalty has been passed prior to making an application, then 'B' shall not be less than the penalty so awarded;  
(b) In case more than one proceeding arising from the same cause of action has been initiated against the applicant, the IA shall be increased by 20%;
3. In case of grant of confidentiality, the IA arrived in accordance with this Schedule shall, be further reduced as follows, -
  - i. those marked first in priority status may be granted reduction of up to or equal to ninety percent of the IA;
  - ii. those marked second in priority status may be granted reduction of upto or equal to fifty percent of the IA; and
  - iii. those marked third or subsequent in the priority status may be granted reduction upto or equal to twenty five percent of the IA.
4. The amount which is finally approved by the Panel of Whole Time Members is the **SA**.
5. Notwithstanding anything in this Schedule, -
  - i. where a compounding application has been filed in respect of an offence under securities laws for non-payment of penalty, the proposal agreeing to the composition of the offence may be made to the court in lieu of such penalty and interest as deemed appropriate along with legal charges as determined by the Board;



- ii. where a compounding application has been filed in respect of an offence under securities laws other than for non-payment of penalty, the proposal agreeing to the composition of the offence may be made to the court in lieu of terms as may be approved by the Panel of Whole Time Members; and
- iii. where a compounding application is filed after framing of the charges by the court, the proposal agreeing to the composition may be made after increasing the amount calculated under this Schedule by atleast twenty-five per-cent along with legal charges and along with any other terms as may be approved by the Panel of Whole Time Members.

### CHAPTER III

#### PROCEEDING CONVERSION FACTOR

The values assigned on the basis of the stage of the proceedings, as on the date of the application, shall be the PCF as per Table I:

Provided that where multiple proceedings arising out of the same cause of action are sought to be settled, the value of the proceeding which is at the most advanced stage, irrespective of the stage of progress of the other proceedings, shall be taken as the PCF.

#### TABLE- I

##### PCF

STAGE OF THE PROCEEDING(S) WHEN THE SETTLEMENT APPLICATION IS MADE		VALUE OF PCF
a.	Voluntary or for seeking settlement with confidentiality	0.65
b.	Pre- issue of the notice to show cause (including applications filed on receipt of the settlement notice/summary settlement notice) [Or Compounding application filed pre-summoning]	0.75
c.	Post-issue of the first notice to show cause pertaining to any pending proceeding in the same cause of action (including applications filed after period provided in settlement notice) [Or Compounding application filed before the framing of charge]	0.85
d.	Proceeding pending after the submission of the report by the Designated Authority [Or Compounding application filed after framing of charge]	0.9
e.	Proceedings pending after passing of a final order imposing penalty or issuing civil and administrative directions, as the case may be	1.10
f.	Proceedings pending after the passing of the order by the Securities Appellate Tribunal or Court	1.20

**CHAPTER-IV****REGULATORY ACTION FACTOR -VALUE FOR ALL ORDERS AND REGULATORY DIRECTIONS**

The sum of all the values assigned to the order and regulatory direction(s) issued in the past, if any, shall be 'RAF'

$$\text{'RAF'} = X + Y$$

**"TABLE II -VALUE for ORDERS AND REGULATORY DIRECTIONS ISSUED X"**

\* To also include those orders and directions which have been stayed by the Securities Appellate Tribunal or Court, as on the date of the application. In case multiple proceedings have been initiated for the same cause of action, the value shall be added for each final order passed.

<b>ORDERS AND REGULATORY DIRECTIONS ISSUED TO THE APPLICANT</b>	<b>X PER ORDER</b>
Exonerated cases (i.e. cases where applicant was exonerated in an order or appeal or review) and any settlement order involving confidentiality	0
Any other Settlement Order	0.01
<b>ALL OTHER ORDERS (EXCEPT FOR WHICH THE APPLICATION IS FILED)</b>	
Cease and desist order	0.02
Final order issued against other persons associated with the securities markets	0.05
Final order issued against an intermediary or securities market infrastructure institutions* or listed companies, and their principal officers	0.075

\*In this schedule an '*intermediary or securities market infrastructure institutions*' includes any person required by securities laws to be registered or recognised by the Board.

**TABLE III- VALUE FOR ORDER OR DIRECTION PASSED OR ISSUED FOR WHICH THE APPLICATION IS FILED – Y**

<b>FINAL ORDER AGAINST INTERMEDIARY OR SECURITIES MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTION, FOR WHICH APPLIED</b>	<b>FINAL ORDER AGAINST ANY PERSON OTHER THAN INTERMEDIARY OR SECURITIES MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTION, FOR WHICH APPLIED</b>	<b>'Y' PER ORDER</b>
Warning issued		0.05
Suspension/Debarment upto 1 month	Debarment upto 6 calendar months	0.1
Suspension/Debarment for 1 month or more, but less than 6 months	Debarment for 6 calendar months or more, but less than 1 year	0.15
Suspension/Debarment for 6 month or more but less than 1 year	Debarment for 1 year or more but less than 2 years	0.2
Suspension/Debarment for 1 year or more but less than 2 years	Debarment for 2 years or more but less than 3 years	0.25
Suspension/Debarment for 2 years or more	Debarment for 3 years or more	0.3

## CHAPTER V

APPLICABLE BASE VALUES AND FACTORS**BV= 1+ SUM OF APPLICABLE BASE VALUES**

- I. While assessing the relevant factors, the IC or HPAC or Panel of WTM's may take into account the following general mitigating factors with a base value of '-0.2' applied once for all or any of them:
  1. The quantum of IA would affect the ability of the applicant to make restitution to investors:  
*Explanation.* - In such cases higher IA may be sought from the officer who is in default.
  2. The applicant had minimal participation in the alleged default;
  3. Proactive and exceptional cooperation, including:
    - a. Prompt and detailed self-identification of suspected or uncovered misconduct;
    - b. Early self-identification of contraventions followed by thorough internal reviews and sharing of discovered facts;
    - c. Substantial assistance to an investigation or inquiry by obtaining and providing evidence.
  4. Acceptance of responsibility and acknowledgement of misconduct to the Board prior to detection and intervention by truthfully admitting the conduct;
  5. Voluntarily employing subsequent substantial corrective measures to avoid recurrence of misconduct;
  6. Where the delay in complying with the reporting requirement was less than 7 days and non-reporting did not result in undue gain or loss to any person;
  7. Voluntary acts of compensation, disgorgement of commission, profits and payment of restitution to investors;
  8. Disclosure made in the incorrect format;
  9. Applicant is a unit of governmental authority including a public-sector unit.
- II. While assessing the relevant factors, the IC or HPAC or Panel of WTM's may take into account the following general aggravating factors with a base value of '0.2' applied once for all or any of them:
  1. Efforts to frustrate or prolong an investigation, inquiry or a civil and administrative proceeding, including settlement proceedings;
  2. Providing inaccurate or misleading testimony or information or wilfully failing to provide information that he was bound to provide;
  3. Misconduct over an extended period of time which is not less than 30 days;
  4. Significant monetary loss to the clients which exceeds in aggregate of Rs 5 crores;
  5. Applicant had failed to heed prior regulatory guidance and prior warnings;
  6. Evidence of planning, pre-meditation or sophisticated means:  
*Explanation:* Conducting default across different jurisdictions, hiding assets or transactions, or both, through the use of fictitious entities, corporate shells or offshore financial accounts ordinarily indicates sophisticated means.
  7. A listed intermediary or securities market infrastructure institution was substantially jeopardized:  
*Explanation.* - A listed intermediary or securities market infrastructure institution shall be deemed to have been substantially jeopardized if as a result of the alleged default:
    - a. it has become insolvent or an application under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 was admitted;
    - b. it was unable on demand to refund fully any public deposit, payment or investment; or

- c. it is so depleted of assets that it is forced to merge with another institution in order to continue active operations.
8. The liquidity of the securities of a publicly traded company was substantially endangered i.e. it was delisted or trading of the company's securities was halted for more than one full trading day;
9. The applicant abused a position of trust or used a special skill, in a manner such that significantly facilitated the commission or concealment of the alleged default:
 

*Explanation 1.* - This factor applies if the applicant occupied and abused a position of trust. It does not apply to an ordinary tippee.

*Explanation 2.* - This factor applies if the applicant's position involved regular participation or professional assistance in creating, issuing, buying, selling, or trading securities or products was used to facilitate significantly the commission or concealment of the default. It does not apply to clerical staff in an organisation; as such position ordinarily does not involve special skill.

*Explanation 3.* - 'Special skill' refers to a skill not possessed by members of the general public and requires professional education, training or licensing, e.g. chartered accountant, advocate, auditor, compliance officer, etc.

*Explanation 4.* - This factor also applies where the applicant has represented himself to hold a position of trust when, in fact, he does not.
10. The applicant was the key-operator, whether or not he himself traded:
 

*Explanation 1.* - A person is a key-operator if he was an organizer or leader of an illegal activity or the main beneficiary of the default:

Provided that, if a person is merely a manager or supervisor (but not an organizer or leader or the main beneficiary) then he is not a key-operator.

*Explanation 2.* - The IC or HPAC or Panel of WTM's may take into account factors such as share of profits, the recruitment of accomplices, the degree of control and authority exercised over others.
11. Exercising management control by use of fraudulent or forged securities or securities issued without appropriate approvals;
12. Reporting of false information.
- III. While assessing the relevant factors, the IC or HPAC or Panel of WTM's may take into account the following factors tending to show the alleged default was deliberate with a base value of '0.25' applied once for all or any of them:
  1. The actions were not in accordance with the applicable internal procedures;
  2. The individual knowingly took decisions relating to the violation beyond his field of competence;
  3. The individual intended to benefit financially from the violation, either directly or indirectly;
  4. The alleged default was repetitive.
- IV. While assessing the relevant factors, the IC or HPAC or Panel of WTM's may take into account the following factor tending to show the alleged default was reckless with a base value of '0.3':
  1. The body corporate or the responsible person, appreciated there was a risk that their actions or inaction could result in a violation of securities laws and failed adequately to mitigate that risk:
 

*Explanation.* - The following shall be deemed to be reckless, -

    - a. failure to appoint competent officials for discharge of their duties, including a compliance officer;
    - b. failure to put in place adequate systemic safeguards; or

- c. failure to put in place a code of conduct.
- V. While considering the various factors and the aggregate base values, the following specific base values shall also be taken into account, -

**TABLE IV- GENERAL BASE VALUES, APPLICABLE IN ALL CASES**

	NATURE OF VIOLATION	BASE VALUE
<b>a.</b>	Fraudulent and unfair trade practice (FUTP); or Insider trading, including tipping (IT); or violation of code of conduct noted in an investigation or inquiry related to FUTP or IT	0.25
	Or	
	FUTP or IT in combination with the violation of code of conduct or any other regulation	0.3
	Or	
	FUTP in combination IT or in combination with a violation of <i>requirement relating to anti-money laundering and know your client.</i>	0.35
	Or	
<b>b.</b>	Failure by a market infrastructure institution or its principal officers to conduct its business in a fair manner.	0.50
	Or	
	Failure by a market infrastructure institution or its principal officers to conduct its business in a fair manner in combination with FUTP or IT or the violation of code of conduct or any other regulation	0.75
		[In case multiple are applicable, only the highest value shall be applied.]
	Factors for volume traded and/or price change for the default	Sum of 'V', 'P' and 'Q', wherever applicable, to be applied to each member of group or the applicant when he acts alone, only if the volume traded or

		price change, quantity traded in respect of the group, of which the applicant is a part of or the applicant when he acts alone, as the case may be, can be calculated from the findings brought out in the investigation report or inquiry or notice to show cause or order, as the case may be.
		In case multiple trading periods are involved, the highest change has to be considered.
c.	Time value of ill-gotten gains*	0.09 × multiple of calendar years from the date of commission of the default
d.	Reputation risk applicable in all settlements without admitting violation of securities laws	All applicants: 0.25
e.	Violation in illiquid scrip	0.3
f.	Persons who are indigent or undergoing liquidation or bankruptcy process or whose resolution/repayment plan has been submitted to the adjudicating authority for approval	- 0.3

**\*Factor 'c' is applicable only in cases where the actual profit and/or loss avoided (approx.) is determinable and disgorgement with interest is not ordered. While calculating the period, the fractions may be ignored.**

**'V' = VALUE FOR THE HIGHEST % OF VOLUME TRADED IN ANY TRADING PERIOD DURING THE ENTIRE PERIOD OF VIOLATION**

**In case of more than one scrip, the scrip with the highest volume traded is to be considered**

**TABLE IVA- SPECIAL BASE VALUES, IN ADDITION TO GENERAL BASE VALUES**

% VOLUME TRADED (ILLIQUID SCRIP)	'V'	% VOLUME TRADED (LIQUID SCRIP)
Upto 50%	0.1	Upto 2%
50 -60%	0.15	2-5%
60-75%	0.2	5-10%
75% or more	0.25	10% or more

**'P' = VALUE FOR HIGHEST % OF PRICE CHANGE DURING THE ENTIRE PERIOD OF VIOLATION**

**In case of more than one scrip, the scrip with the highest price change is to be considered**

**TABLE IVB- SPECIAL BASE VALUES, IN ADDITION TO GENERAL BASE VALUES**

<b>% PRICE CHANGE (ILLIQUID SCRIP)</b>	<b>‘P’</b>	<b>% PRICE CHANGE (LIQUID SCRIP)</b>
Upto 50%	0.1	Upto 5%
50-100%	0.15	5-10%
100-200%	0.2	10-20%
200% or more	0.25	20% or more

**‘Q’ = VALUE FOR HIGHEST % OF PRICE CHANGE, DURING THE PERIOD OF DEFAULT FOR F&O & LEVERAGED PRODUCTS**

**In case of more than one product, the contract with the highest price change is to be considered**

**TABLE IVC- SPECIAL BASE VALUES, IN ADDITION TO GENERAL BASE VALUES**

<b>% PRICE CHANGE</b>	<b>‘Q’</b>
Upto 0.5%	0.1
0.5-1%	0.15
1-5%	0.2
5% or more	0.25

**TABLE V- SPECIAL BASE VALUES, IN ADDITION TO GENERAL BASE VALUES FOR DISCLOSURE AND OPEN OFFER**

<b><u>DEFAULTS</u></b>	
<b>NATURE OF VIOLATION</b>	<b>BASE VALUE</b>
<b>a.</b> In Non-disclosure (including incorrect or incomplete disclosure) charge under any regulation relating to takeover, insider trading or issue or listing of securities in combination with any other charge	0.20
<b>b.</b> In Non-Disclosure (including incorrect or incomplete disclosure) matters: Applicant has made related disclosure under any other regulation or is a body corporate with paid-up equity share capital (including reserves) below Rupees Ten crores (not applicable to companies which are exclusively holding companies)	- 0.5
<b>c.</b> In open offer violations: acquirer not in control of target company, prior to triggering the takeover	0.25

- VI. In cases of multiple applicants where joint and several liabilities exists, a single IA may be based on the factors and the weightages applicable to the default in general, as the IC or HPAC or Panel of WTM's may deem fit and any other factor may also be considered while imposing any limit in respect of amounts that may be required from a particular applicant, in respect of the IA calculated for multiple applicants.

## CHAPTER VI

APPLICABLE BASE AMOUNT

APPLICABLE BA = 'The illegal profits' + 'loss caused to investors' [quantified as per the guidelines, if any, issued by the Board]

Or

The BA as per the Tables in this Chapter,  
whichever is higher.

GENERAL GUIDELINE: In case the applicant is charged for non-disclosure under Regulations relating to Open Offer [SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997, SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and any subsequent similar regulations] and PIT [Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, and any subsequent similar regulations], the highest of the Base Amount arrived at for such charges shall be reduced by 75%.

TABLE-VIBA FOR ALLEGED DEFAULT RELATING TO OPEN OFFER

NATURE OF VIOLATION

BA FOR ACQUIRER AND PERSONS ACTING IN CONCERT

DELAYED OPEN OFFER

RUPEES 25 LAKH

OR

0.25% OF THE OPEN OFFER SIZE, I.E. MAX NUMBER OF SHARES FOR  
WHICH OPEN OFFER MUST BE GIVEN X APPLICABLE OPEN OFFER PRICE,

WHICHEVER IS HIGHER

DELAYED OPEN OFFER

RUPEES 50 LAKH

OR

0.5% OF THE OPEN OFFER SIZE,

WHICHEVER IS HIGHER

(AFTER DIRECTION FROM THE BOARD)

WHERE THE MAKING OF THE OPEN OFFER IS INFRUCTUOUS

INFRUCTUOUS BY AN ACT OF THE

INFRUCTUOUS

I.E. WHEN COMPANY HAS BEEN DELISTED, WHEN OPEN

COMPANY REQUIRED TO MAKE AN

DUE TO OTHER

OFFER IS NOT BENEFICIAL TO SHAREHOLDERS, ETC

OPEN OFFER

REASON,

INCLUDING

WHEN OPEN

OFFER IS NOT

BENEFICIAL TO

SHAREHOLDERS

RUPEES 1 CRORE

OR

OPEN OFFER SIZE,

WHICHEVER IS HIGHER

ANY AMOUNT

BETWEEN THE

MINIMUM

PENALTY TO

PROBABLE COST

OF OPEN OFFER

AS



RECOMMENDED  
BY THE  
CORPORATE  
FINANCE  
DEPARTMENT OF  
THE BOARD

**TABLE-VII**

**BA FOR ALLEGED DEFAULT RELATING TO DISCLOSURES UNDER SECURITIES EXCHANGE BOARD OF  
INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS -1997/2011**

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING OR VOTING RIGHTS ACQUIRED OR DISPOSED BUT NOT DISCLOSED OR PERCENTAGE OF ENCUMBERED SHARES BUT NOT DISCLOSED, ETC.	<b><u>BA FOR VIOLATION OF</u></b>		
	<b>REGULATION 7 OF 1997 REGULATIONS</b>	<b>REGULATION 8 OF 1997 REGULATIONS</b>	<b>REGULATION 8A OF 1997 REGULATIONS</b>
	<b>OR</b>	<b>OR</b>	<b>OR</b>
	<b>REGULATION 29 OF 2011 REGULATIONS</b>	<b>REGULATION 30 OF 2011 REGULATIONS</b>	<b>REGULATION 31 OF 2011 REGULATIONS</b>
	<b>(I)</b>	<b>(II)</b>	<b>(III)</b>
Less than 2%		Rupees 2 lakh + Rupees 5,000/- For every three months delay <sup>#</sup> or part thereof	
2% to less than 5%		Rupees 5 lakh + Rupees 10,000/- For every three months delay or part thereof	
5% to less than 10%		Rupees 10 lakh + Rupees 15,000/- For every three months delay or part thereof	
10 % to less than 15%		Rupees 15 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc. + Rupees 20,000/- For every three months delay or part thereof	
15% and above		Rupees 20 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc. + Rupees 25,000/- For every three months delay or part thereof	

**Notes to Table VII:**

1. Table VII is not applicable in cases where the disclosure related violation is in combination with FUTP or IT.

*Explanation:* Dealing while in possession of material financial or shareholding information may be treated as IT.

2. The BA for violation at (II) shall only be as per the lowest slab, irrespective of change in shareholding over the reporting period. In case of violations related to disclosures that are required to be made annually\ the amount for delay for every three months or part thereof shall be computed only for the first disclosure violation. In case the noticee complies with the annual reporting requirements for a few years, such compliance will not result in a higher amount than would have otherwise be calculated for continuous violations.
3. The period of delay is to be calculated from the last day, when the disclosure ought to have been made, as required by the regulations.

**TABLE VIII**

**BA – ALLEGED DEFAULT RELATING TO TRANSACTION SPECIFIC DISCLOSURES UNDER REGULATIONS 13(3), 13(4), 13(4A) AND CORRESPONDING 13 (6) OF 1992 PIT REGULATIONS [INCLUDES, CORRESPONDING TRANSACTION SPECIFIC DISCLOSURES UNDER REGULATIONS OF 2015 PIT REGULATIONS]**

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING OR VOTING RIGHTS ACQUIRED OR DISPOSED BUT NOT DISCLOSED OR PERCENTAGE OF ENCUMBERED SHARES BUT NOT DISCLOSED, ETC.	BA
Less than 2%	Rupees 2.5 lakh + Rupees 7,500/- For every three months delay or part thereof
2% to less than 5%	Rupees 6 lakh + Rupees 12,500/- For every three months delay or part thereof
5% to less than 10%	Rupees 12 lakh + Rupees 17,500/- For every three months delay or part thereof
10 % to less than 15%	Rupees 18 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc. + Rupees 22,500/- For every three months delay or part thereof

15% and above

Rupees 25 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc.

+

Rupees 25,000/- For every three months delay or part thereof

**Notes to Table VIII:**

1. In cases of disclosure related violations by connected persons or by key managerial persons, the BA may be increased by 25%.
2. Table VIII is not applicable in cases where the disclosure related violation is in combination with FUTP or IT.

*Explanation:* Dealing while in possession of material financial or shareholding information may be treated as IT.

**TABLE IX****BA - DISCLOSURES RELATED VIOLATIONS NOT COVERED IN TABLES VII AND VIII****NATURE OF ALLEGED DEFAULT****BASE AMOUNT****TYPE OF DISCLOSURE RELATED VIOLATION****PIT REGULATIONS**

Periodical and other disclosures

Rupees 5 lakh

+

Rupees 5,000/- for every three months delay or part thereof, if applicable

**OPEN OFFER REGULATIONS**

Reporting requirements or disclosures for which exemptions are available, except cases of non-compliance of a condition precedent for availing exemption would result in triggering of an open offer

Rupees 5 lakh

+

obligation

Rupees 10,000/- for every three months delay or part thereof, if applicable

(The Regulation 6 of 1997 Regulations are dated and no amount may be imposed for its violation, except in case of standalone violations of Regulation 6 the minimum SA may be applicable)

**VIOLATIONS UNDER REGULATIONS RELATED TO FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS**

Failure to provide information

Rupees 20 lakh per default

Intimation of material changes

Rupees 10.0 lakh per default

## RESIDUARY

Code of conduct reporting requirements

or

Rupees 5 lakh

Disclosures on appointment of director

+

or

Rupees 10,000/- for every three months delay

Any other disclosure related violations that are not detailed in this

or part thereof, if applicable

Chapter, if deemed appropriate

## Notes to Table IX:

1. In cases of disclosure related violations by key managerial persons, the Benchmark Amount may be increased by 25%.
2. Table IX is not applicable in cases where the disclosure related violation is in combination with FUTP or IT.

*Explanation:* Dealing while in possession of material financial or shareholding information may be treated as IT.

TABLE-XRESIDUARY BA, FOR EACH UNIT OF ALLEGED DEFAULT FOR EACH APPLICANT OR ON JOINT LIABILITY BASIS (AS PER THE SUM OF APPLICABLEAMOUNTS IN CASE OF JOINT APPLICANTS)

	INDIVIDUAL (PRINCIPAL OFFICERS NOT INCLUDED)  (I)	BODY CORPORATE & FIRM (AND PRINCIPAL OFFICERS IN CASES RELATING TO JOINT LIABILITY WITH THE BODY CORPORATE /FIRM) (II)	PRINCIPAL OFFICERS & COMPLIANCE OFFICERS [WHEN NOT IN II, IV-VII] (III)	SECTION 15B AND 15F OF SEBI ACT & SIMILAR DEFAULTS (AND PRINCIPAL OFFICERS IN CASES RELATING TO JOINT LIABILITY WITH THE INTERMEDIA RY) (IV)	FAILURE IN REDRESSING INVESTOR GRIEVANCES (AND PRINCIPAL OFFICERS IN CASES RELATING TO JOINT LIABILITY WITH THE INTERMEDIA RY/ ISSUER) (V) (FOR DELAY REDUCE TO 1/4)	MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS (AND PRINCIPAL OFFICERS IN CASES RELATING TO JOINT LIABILITY WITH THE INSTITUTION) (VI)	FUND RELATED DEFAULTS (AND PRINCIPAL OFFICERS IN CASES RELATING TO JOINT LIABILITY WITH THE FUND) (VII)
BA WHERE: DEFAULT RELATE TO FUTP OR IT,	RUPEES 15 LAKHS	RUPEES 1 CRORES	RUPEES 45 LAKHS	RUPEES 15 LAKHS	RUPEES 30 LAKHS	RUPEES 5 CRORES	RUPEES 33 LAKHS  OR

FALSE/ MISLEADING/ INCORRECT/IN COMPLETE DISCLOSURES IN OFFER DOCUMENTS,							0.01% OF THE AVERAGE ASSET UNDER MANAGEMENT, AT TIME OF VIOLATION
							OR
FAILURE BY MARKET INFRASTRUCT URE INSTITUTIONS TO CONDUCT BUSINESS IN THE REQUIRED MANNER,							0.5% OF THE AVERAGE NET WORTH, AT TIME OF VIOLATION,
							WHICHEVER IS HIGHER
A RECKLESS VIOLATION,							
OR							
A DISGORGEMENT/REFUND IN EXCESS OF RUPEES 1 CRORE (M)							
BENCHMARK WHERE VIOLATION INVOLVED AT (M) AND, - SUCH VIOLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY –	RUPEES 60 LAKHS	RUPEES 3 CRORES	RUPEES 2 CRORES	RUPEES 60 LAKHS	RUPEES 80 LAKHS	RUPEES 10 CRORES	RUPEES 60 LAKHS
							OR
(I) RESULTED IN SUBSTANTIAL LOSSES TO OTHER PERSONS,							0.05% OF THE AVERAGE ASSET UNDER MANAGEMENT, AT TIME OF VIOLATION
							OR
(II) CREATED A SIGNIFICANT RISK OF SUBSTANTIAL LOSSES TO OTHER PERSONS, OR							0.075% OF THE AVERAGE NET WORTH, AT TIME OF VIOLATION, WHICHEVER IS HIGHER

(III) AFFECTED THE INTEGRITY OF THE SECURITIES MARKETS <u>(N)</u>							
RESIDUARY <u>(O)</u>	RUPEES 3	RUPEES 15	RUPEES 10	RUPEES 3	RUPEES 6	RUPEES 3	RUPEES 15 LAKHS
	LAKHS	LAKHS	LAKHS	LAKHS	LAKHS	CRORES	
OR							
0.001% OF THE AVERAGE ASSET UNDER MANAGEMENT, AT TIME OF VIOLATION							
OR							
0.01% OF THE AVERAGE NET WORTH, AT TIME OF VIOLATION,							
WHICHEVER IS HIGHER							

**Note to Table X:**

1. In case of applicability of more than one BA, the highest is to be considered.
2. In this Schedule, 'Principal Officer' means a person that may be covered under Section 27 of the SEBI Act, as amended by the Finance Act, 2018.
3. 'Fund' means an AIF, MF, CIS, and any other pooling arrangement required to be registered with the Board.
4. 'Body corporate' in (II) of this Table includes, any applicant not covered in (I) and (III) to (VII).

**CHAPTER VII****REPETITIVE NATURE OF DEFAULT**

- I. The counts of defaults may be selected using one or more or a combination of the methods indicated in this Chapter.  
*Explanation.* - Different methods may be used in respect of different persons in the same cause of action as may be required for arriving at a reasonable IA.
- II. In general, the unit of alleged default may be selected from either of, or a combination of, the following, -
  - i. the (approx.) number of purchase or sale transaction,
  - ii. the (approx.) number of individual deceptions attempted,
  - iii. the (approx.) number of investors involved, or
  - iv. 'Course of conduct' standard

-whereby each counts amounts to a complete violation. Discretion may be used to apply a different standard that is less prejudicial to a person after taking into account the interest of the investors in securities:

Provided that, where a large number of counts of a default are noted, for arriving at a reasonable IA a less prejudicial standard of selecting the unit of default may be applied.

*Explanation.* - In respect of a default relating to a report or statement, -

- i. each person to whom a misleading report was sent or statement made may involve a separate “act”;
- ii. each distinct misleading report or statement made may be a separate “act”;
- iii. each distinct misleading statement within a report may be a separate “act”;
- iv. the course of conduct standard in respect of all or any such reports or statements; or
- v. a combination of i, ii, iii and iv above.

III. **Course of Conduct standard:** Depending on the facts and circumstances of a case, for the purpose of arriving at a reasonable IA, “course of conduct” standard in which multiple counts of a violation are aggregated and counted as a single violation for purposes of calculating IA may be applied.

*Explanation 1.* - It may be reasonable to aggregate multiple counts of a default if, -

(a) the conduct did not involve manipulative, fraudulent or deceptive intent or insider trading, except where the recommended IA would otherwise be extremely disproportionate to the conduct;

*Explanation.* - “disproportionate” and “reasonable” refer to the appropriateness vis-à-vis the deterrence sought to be achieved and not appropriateness vis-à-vis the illegal profit made by the applicant or loss caused to investors.

(b) the conduct did not result in substantial injury to the rights of public investors, or if restitution was made in such cases; and

(c) the violations resulted from a systemic problem or cause that has been corrected.

*Explanation 2.* - Depending on the facts and circumstances, the units of violation may be based on how long the violations continued, however no uniformity of the period of time (daily, weekly, fortnightly, monthly, yearly) is required. The multiple counts of violation acts may be combined into one or more than one course of conduct.

### SCHEDULE III

#### Part-A

(See regulation 16)

#### Format

To

Date

Address

#### **Sub: Notice of summary settlement in the matter of .....**

During the course of investigation/ inspection/ inquiry/ audit in the matter of..... the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has *prima facie* observed that you have violated the following provisions of the securities laws:

- (i) .....
- (ii) .....
- (iii) .....
- (iv) .....

Extracts of the findings are enclosed.

2. In view of the aforesaid, probable proceedings against you under....(*relevant provisions under which the proceedings may be initiated or continued*) may be initiated or continued .
3. Notwithstanding anything contained in this notice, the Board reserves the right to modify the proceedings and charges to be brought against you and this notice shall not confer any right to seek settlement or avoid any action initiated by the Board.

4. Subject to Regulation 5 of the SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 the aforesaid proceedings to be initiated may be settled and disposed of upon filing of a settlement application under Chapter-II of the SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 upon remittance of a settlement amount of Rs. ....to SEBI in terms of ..... (provision) of SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 within 30 calendar days from the date of receipt of this notice and upon complying with the following non-monetary terms (if applicable):

(i) .....

(ii) ..... (*please specify any other terms*)

5. **In case the settlement application is not filed or the settlement amount is not remitted and/or undertaking in respect of other non-monetary terms is not furnished or other non-monetary terms are not complied with to the satisfaction of the Board or the settlement application is withdrawn, the specified proceedings may be initiated or continued, as the case may be and you shall be permitted to file a settlement application only at the next stage in respect of proceedings pending before a Court or a tribunal, after conclusion of proceedings before the Adjudicating Officer or the Board, as the case may be.**

Name, designation and signature

Encl: As above

### **Part-B**

(*See regulation 18*)

### **Format**

To

Date

Address

### **Sub: Notice of settlement in the matter of .....**

During the course of investigation/ inspection/ inquiry/ audit in the matter of..... the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has *prima facie* observed that you have violated the following provisions of the securities laws:

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

(iv) .....

Extracts of the findings are enclosed.

2. In view of the aforesaid, probable proceedings against you under....(*relevant provisions under which the proceedings may be initiated or continued*) may be initiated or continued.
3. Notwithstanding anything contained in this notice, the Board reserves the right to modify the proceedings and charges to be brought against you and this notice shall not confer any right to seek settlement or avoid any action initiated by the Board.
4. Subject to regulation 5 of the SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, the aforesaid proceedings to be initiated may, be settled and disposed of upon filing of a settlement application under Chapter-II of the SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 within 15 calendar days from the date of receipt of this notice.
5. **If the settlement application is not filed, the Board may initiate any proceedings against you in accordance with law and you shall be permitted to file a settlement application only at the next stage in respect of proceedings pending before a Court or a tribunal, after conclusion of proceedings before the Adjudicating Officer or the Board, as the case may be.**

Name, designation and signature

Encl: As above



**SCHEDULE IV****(see Regulation 19)****Application for confidentiality**

1. The application for confidentiality shall be in the format convenient to the applicant and shall inter-alia, include the following, -
  - i. name and address of the applicant or its authorized representative as well as of all other known participants involved in the alleged default;
  - ii. the address of the applicant for communication including the telephone numbers and the e- mail address, etc.;
  - iii. a detailed description of the alleged arrangement, including its aims and objectives and the details of activities and functions carried out for securing such aims and objectives;
  - iv. the commencement and duration of the default;
  - v. the names, positions, office locations and, wherever necessary, home addresses of all persons who, in the knowledge of the applicant, are or have been associated with the alleged defaulters, including those persons who have been involved on behalf of the applicant;
  - vi. the details of other authorities, forums or courts, if any, that have been approached or are intended to be approached in relation to the alleged violation;
  - vii. a descriptive list of evidence regarding the nature and content of evidence provided in support of the application for confidentiality; and
  - viii. any other material information as may be directed by the Board.

(Signature of the applicant)

(Stamp and Seal of body corporate applicant)

**Verification**

I, .....son/daughter/wife of (Name in block letters)

Shri .....being the applicant/authorised representative (in case of body corporate) of  
 ..... do hereby verify and affirm on oath that this application and the contents thereof are true to  
 my knowledge and belief and as per the records and that I have not suppressed any material facts and shall keep  
 the Board informed without delay, of any other relevant information that may come to my notice.

(Signature of the applicant)

Date:

Place :

2. The undertaking and waiver as specified in Part C of Schedule-I shall be annexed to the application for confidentiality.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./378/18]